नई दिल्ली

02 जुलाई, 2026 गुरूवार

मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 92

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com

Email : timesofpedia@gmail.com

स्टोक्स के लिए आसान नहीं होगा संन्यास के बाद मैदान से दूर रहना : सचिन 07

संक्षिप्त वार्ता

अगस्त में होंगे ऑनलाइन टीईटी एग्जाम

भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने और शिक्षकों की योग्यता परखने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानि टीईटी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अधिकारियों की

मानें तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आगामी अगस्त महीने में इस ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन संभावित है। वहीं इस बार परीक्षा के सफल संचालन के लिए मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों को सौंपी जा रही है। इस परीक्षा में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग दोनों के मिलाकर लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों के शामिल होने का अनुमान है। कर्मचारी चयन मंडल के जनसंपर्क अधिकारी विशाल जोशी के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत करीब 70 हजार और जनजातीय कार्य विभाग के तहत लगभग 35 हजार शिक्षक इस परीक्षा की पात्रता श्रेणी में आते हैं। कर्मचारी चयन मंडल वर्तमान में शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परीक्षार्थियों की वास्तविक संख्या का सटीक विश्लेषण कर रहा है।

लाहौर में निजी ट्यूशन सेंटर की छत ढही: 14 बच्चों की मौत, 20 घायल

लाहौर। यहां मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। घनी आबादी वाले काहना नौ क्षेत्र के बस्ती ईदगाह इलाके में स्थित एक निजी ट्यूशन सेंटर की छत अचानक ढह गई। इस भीषण दुर्घटना में 14 स्कूली बच्चों की दुखद मौत हो गई, जबकि कम से कम 20 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय, सात से तेरह वर्ष की आयु के मासूम बच्चे कक्षाओं में बैठे हुए थे, जो इमारत के मलबे के नीचे दब गए। पुलिस और बचाव टीमों के शुरूआती आकलन के अनुसार, यह ट्यूशन सेंटर एक निमार्णाधीन इमारत के अंदर संचालित हो रहा था, जो सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन था।

दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर के बाद लगी भीषण आग

गुंटूर, । आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बुधवार को प्रतिपाडु मंडल में बोयापालेम के पास एक सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जलकर मौत हो गई। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे बोयापालेम गांव में हुआ। मीडिया रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि एक ट्रक कुरनूल से गुंटूर की ओर दूसरी गुंटूर से चिलकलुरिपेट की ओर से आ रहे वाहन की आमने-सामने टक्कर हो गईं। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग में दो ड्राइवर और एक हेल्पर जिंदा जल गए। हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, क्योंकि दोनों लॉरी पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थीं।

7000 से अधिक पेट्रोल पंपोंमें लागू हुई नई दरें

पेट्रोल 5 और डीजल 3 रुपये सस्ता हुआ

निजी क्षेत्र की तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की है। कंपनी का मानना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। नायरा एनर्जी ने यह फैसला मध्य पूर्व में तनाव कम होने और कच्चे तेल की वैश्विक आपूर्ति सामान्य होने के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को देखते हुए किया है।

वेब वार्ता, मुम्बई

गौरतलब है कि देशभर में नायरा एनर्जी के 7000 से अधिक पेट्रोल पंपों पर यह नई दरें लागू हो गई हैं। हालांकि, विभिन्न स्थानों पर लगने वाले स्थानीय करों (वैट) के कारण पेट्रोल और डीजल की अंतिम कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं। जबकि नायरा एनर्जी ने दाम घटाकर उपभोक्ताओं को राहत दी है, भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल), इंडियन ऑयल (आईओसी) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) जैसी सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने फिलहाल अपनी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया है।

गौरतलब है कि नायरा ने ही कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचने पर सबसे पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए थे। उस समय पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर महंगा किया गया था। कंपनी का यह कदम तब आया था जब वैश्विक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया था। अभी अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरों के कारण वैश्विक कच्चे तेल बाजार में नरमी देखी जा रही है। आज 1 जुलाई को कच्चा तेल मामूली 0.33 फीसदी की उछाल के साथ 73 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो उच्च स्तरों से काफी कम है। इससे तेल कंपनियों पर कच्चे तेल की खरीद का दबाव काफी हद तक कम हो गया है।

गौरतलब है कि सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरी बार 25 मई को कीमतों में बढ़ोतरी की थी, जिसमें पेट्रोल के दाम कुल 7.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 7.60 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाए गए थे। इन बढ़ोतरी के बाद से आम जनता लगातार कीमतों में कटौती का इंतजार कर रही थी। देश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग-अलग हैं।

चंडीगढ़ में पेट्रोल सबसे सस्ता 101.54 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि हैदराबाद में यह 115.69 रुपये प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नोएडा में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर पर उपलब्ध है। दूसरी ओर डीजल की बात करें तो चंडीगढ़ में इसकी कीमत 89.47 रुपये प्रति लीटर है, वहीं हैदराबाद में यह 103.82 रुपये प्रति लीटर के साथ सबसे महंगा है। नायरा एनर्जी द्वारा की गई यह कटौती उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जहां कंपनी के पेट्रोल पंप मौजूद हैं।

1 जुलाई से कॉमर्शियल सिलेंडर 180 रुपए सस्ता

नई दिल्ली। 1 जुलाई यानी बुधवार से देश में आम आदमी की जेब, रसोई और सफर से जुड़े 6 बड़े नियम बदल गए हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर 180 रुपए सस्ता तो पासपोर्ट बनवाना महंगा हो गया है। ट्रेन में बिना टिकट सफर करने पर दोगुना जुमार्ना लगेगा। तेल कंपनियों ने 1 जुलाई से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में औसतन 180 तक की बड़ी कटौती कर दी है। हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में अब नया दाम 2930 .00 हो गया है जो पहले 3113.50 था यानी 183.50 रुपए की कमी आई है। कोलकाता में नई कीमत 3081.50 है जो पहले 3255 .50 थी यानी 174 रुपए की कमी, मुंबई में पुराना दाम 3067 .50 था जो अब घटकर 2885 .50 रुपए रह गया है यानी 182 .00 की कमी और चेन्नई में पहले इसकी कीमत 3283 .00 थी जो अब कम होकर 3106 रुपए हो गई है यानी 177 की कमी।

अमरनाथ यात्रा: रजिस्ट्रेशन शुरू, पंजीकरण के लिए भक्तों का उमड़ा सैलाब

शुक्रवार को रवाना होगा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था

श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू-कश्मीर में तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में, बुधवार से जम्मू में यात्रियों के लिए मौके पर पंजीकरण और आरएफआईडी कार्ड जारी करने की प्रकिया शुरू हुई है।

वेब वार्ता, जम्मू

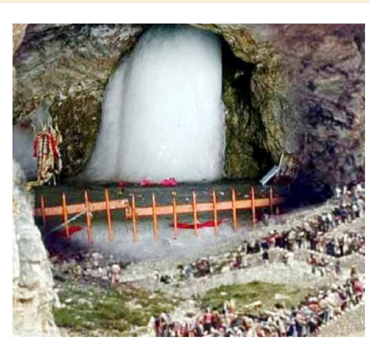

प्रक्रिया शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारों में खड़े दिखे, जिससे यात्रा को लेकर उनका जबरदस्त उत्साह साफ दिखा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शुक्रवार को तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले है।

भक्तों ने यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की सराहना की। एक उत्साहित तीर्थयात्री ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पहले बैच में मौका मिलेगा। मैं काफी समय से कोशिश कर रहा था। एक अन्य अनुभवी यात्री ने पिछली बार के मुकाबले इस बार की व्यवस्थाओं को और बेहतर बताया। कुछ श्रद्धालुओं ने पंजीकरण और आरएफआईडी कार्ड प्राप्त करने में थोड़ी प्रतीक्षा का अनुभव साझा किया, लेकिन उनका कहना था कि इसके बाद बाबा बफानी के दर्शन का विश्वास और सुकून मिल जाता है।

इसी बीच, यात्रा का पहला जत्था रवाना होने से पहले श्रीनगर के ट्रांजिट कैंपों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है। कई पहली बार यात्रा पर आए भक्त बेहद उत्साहित दिखे। एक महिला तीर्थयात्री ने अपनी आस्था व्यक्त कर कहा, मैं बाबा भोलेनाथ में आस्था लेकर आई हूं। उन्होंने हमें बुलाया है और वही दर्शन कराएंगे। उन्होंने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की, बताते हुए कि कैंप में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।

उस दिन की जा सकती है वापसी

गौरतलब है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा के लिए दो मुख्य मार्ग हैं पहलगाम मार्ग, जिसमें मंदिर तक पहुंचने में लगभग चार दिन लगते हैं, और बालटाल मार्ग, जो छोटा है और अक्सर उसी दिन वापसी की जा सकती है।

नोएडा एयरपोर्ट से भोपाल समेत 11 नए शहरों के लिए इंडिगो की फ्लाइट शुरू

वेब वार्ता, ग्रेटर नोएडा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश के 11 शहरों की कनेक्टिविटी बुधवार से और मजबूत हो गई। इंडिगो एयरलाइन बुधवार से नवी मुंबई समेत भोपाल, जयपुर, देहरादून, धर्मशाला समेत अन्य शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू की। अभी तक इंडिगो की विमान सेवा हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, जम्मू आदि शहरों में ही उपलब्ध थी। नए शहरों के जुड़ने से एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से यात्री सेवाओं की शुरूआत के साथ इंडिगो ने लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु और अमृतसर के लिए विमान सेवा शुरू की थी। एक जुलाई से शुरू होने वाली विमान सेवा के लिए जयपुर के लिए 3325 रुपए प्रति यात्री, लखनऊ के लिए 3394 से लेकर 5979 रुपए में, भोपाल के लिए 5297 रुपए, जयपुर के लिए 4375 रुपए, धर्मशाला के लिए 5028 रुपए, देहरादून के लिए 2888, चंडीगढ़ के लिए 4400 रुपए में टिकट उपलब्ध है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून को इंडिगो ने जम्मू और अकासा एयर ने बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए अपनी सेवा शुरू की थी, लेकिन एक जुलाई से नोएडा एयरपोर्ट कई नए शहरों को विमान सेवा से जोड़ने जा रहा है। इसके शुरू होने से नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों को सहूलियत होगी। वे नोएडा एयरपोर्ट से देश के 16 शहरों के लिए यात्रा कर सकेंगे। हालांकि बरेली के लिए सप्ताह में चार दिन व किशनगढ़ के लिए सप्ताह में तीन दिन विमान सेवा उपलब्ध होगी।

एयरपोर्ट पर रोजाना टेकआफ और लैंड करने वाले विमानों की संख्या 48 तक पहुंच जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिले, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं।

जरूरत के अनुरूप कर लिया है स्टाफ की संख्या

बुधवार से फ्लाइट और यात्री संख्या में वृद्धि को देखते हुए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. व एयरलाइन कंपनियों ने अपने स्टाफ की संख्या को जरूरत के अनुरूप कर लिया है। नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, भोपाल, देहरादून, पंतनगर, धर्मशाला, लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़, बरेली शामिल हैं। किशनगढ़ के लिए गुरुवार को विमान सेवा उपलब्ध होगी। हैदराबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, जम्मू के लिए पहले से ही विमान सेवा संचालित हो रही है। 16 जून से शुरू हुई अकासा एयर की विमान सेवा नोएडा एयरपोर्ट से अभी दो शहरों के लिए ही संचालित हो रही है। इसमें नवी मुंबई और बेंगलुरु शामिल हैं। नोएडा एयरपोर्ट से यात्री सेवा के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी यापल के साथ कर रखा है, लेकिन अभी एयरलाइन ने नोएडा एयरपोर्ट से अपनी यात्री सेवाओं की शुरूआत नहीं की है।

महोत्सव का शुभारंभ

सिवनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिवनी में खेतों में धान के पौधों को रोप कर धान महोत्सव का शुभारंभ किया।

पीएम मोदी ने डॉक्टर और सीए को बताया विकास और स्वास्थ्य के दो मजबूत स्तंभ

पीएम समेत कई दिग्गजों ने दी डॉक्टर्स और सीए डे पर शुभकामनाएं

वेब वार्ता, नई दिल्ली। आज 1 जुलाई को देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े इन दो अहम क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शुभकामनाएं दीं। नेताओं ने डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डॉक्टरों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका सेवा भाव देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। ये देश के विकास और स्वास्थ्य के दो मजबूत स्तंभ हैं।

प्रधानमंत्री के अनुसार, देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है, जबकि एमबीबीएस और पीजी मेडिकल सीटों में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। इससे चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर बने हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में डॉक्टर प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, मेडिकल रिसर्च और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीए समुदाय को भारत की आर्थिक प्रगति का भरोसेमंद सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि वित्तीय पारदर्शिता, उद्यमिता को बढ़ावा देने और निवेशकों का विश्वास मजबूत करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उनके प्रयासों से देश में बेहतर कारोबारी माहौल तैयार हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वित्तीय अनुशासन और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित कर देश की आर्थिक प्रगति को गति देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें वित्तीय ईमानदारी का आधार स्तंभ बताया।उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सीए की पेशेवर दक्षता और निष्ठा विकसित भारत के संकल्प को मजबूत आधार प्रदान कर रही है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को सशक्त बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सीए समुदाय के योगदान की सराहना की।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर नेताओं ने महान चिकित्सक और भारत रत्न डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती एवं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों को स्वस्थ समाज की आधारशिला बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मनोहर लाल समेत कई नेताओं ने भी डॉ. रॉय के योगदान को याद किया।

मध्यप्रदेश ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा की दिशा में उठाया बड़ा कदम

वेब वार्ता, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत कर दी है। मध्यप्रदेश, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरूआत कर रहा है। उन्होंने बताया कि दावोस में की गई घोषणा के अनुरूप प्रदेश, 24 घंटे हरित ऊर्जा देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव 24 घंटे नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में आयोजित प्री-बिड मीटिंग को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। नई दिल्ली में हुई बैठक में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव श्री मनु श्रीवास्तव तथा विभिन्न कपंनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में सबसे कम सौर टैरिफ स्थापित कर भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। शाजापुर-नीमच सोलर पार्कों ने 2 .14 रूपए प्रति यूनिट का प्रदेश में सबसे कम टैरिफ अर्जित किया। हाल ही में मुरैना की 4 घंटे की स्टोरेज प्लस परियोजना के लिए 2 .70 रूपए प्रति यूनिट पर पीपीए हुआ, यह देश की सबसे प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में से एक है।

जनरल धीरज सेठ ने संभाला थलसेना प्रमुख का पदभार

वेब वार्ता, नई दिल्ली। भारतीय सेना के नए थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बुधवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय मुख्यालय में आयोजित गार्ड ऑफ ऑनर समारोह में एक अत्यंत भावुक और गौरवपूर्ण क्षण दिखाई दिया। गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त करने के बाद, जनरल सेठ ने अपने पिता, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ, को सैन्य सैल्यूट किया। पिता ने भी पलटकर सैल्यूट किया, जिसके बाद नए सेना प्रमुख ने अपने पिता सहित वहां मौजूद परिजनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। यह दृश्य उपस्थित सैन्य अधिकारियों, जवानों और अतिथियों के लिए विशेष प्रेरणा का केंद्र रहा।

संपादकीय

चंदा-चढ़ावा कांड बेनतीजा

उप्र के पुलिस महानिदेशक रहे डॉ. विक्रम सिंह और सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा के आकलन हैं कि राम मंदिर चंदा-चढ़ावा चोरी का मामला शायद ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचे, क्योंकि जांच के नाम पर जो किया जा रहा है, उसमें कई छिद्र हैं और वह सवालिया भी है। बड़ी आरामदेह जांच चल रही है। जांच के नाम पर तमाशा किया जा रहा है। अहम और संदेहास्पद सवाल यह है कि जिन 8 आरोपितों को पुन: 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, उनकी रिमांड पुलिस ने क्यों नहीं मांगी? यदि रिमांड नहीं है, तो आरोपितों से पूछताछ, सवाल-जवाब कैसे किए जाएंगे? पूछताछ नहीं होगी, तो कथित अपराधियों से बरामदगी कैसे होगी? अपराध के सुराग और नेटवर्क कैसे खुलेंगे? बरामदगी तभी महत्वपूर्ण और कानूनी है, जब आरोपित कबूल करें और खुलासा करें कि चोरी का धन, आभूषण आदि कहां रखे हैं? पैसे का कहां निवेश किया गया है? जब तक ये जानकारियां पुष्ट, सत्यापित नहीं होंगी, तब तक अपराध साबित नहीं किया जा सकता। ये दोनों शीर्ष पुलिस अधिकारी मानते हैं कि जो कार्रवाई ट्रस्ट ने की और करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी विशेष जांच टीम से भी छिपाई और प्राथमिकी 20 दिन के बाद दर्ज कराई गई, इन सबके बीच इतने छिद्र हैं कि जांच किसी निष्कर्ष या नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद क्षीण है। गौरतलब है कि विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने खुलासा किया है कि बीती 5 जून को राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद प्राथमिक जांच कराई। पुलिस की मदद ली गई और आरोपित अविनाश शुक्ला के घर से करीब पांच लाख रुपए नकदी का काला बैग बरामद किया गया, लेकिन 7 जून को ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बंसल ने चोरी से इंकार किया। कहा कि कुछ उल्लेखनीय बात नहीं हुई। पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह इसे ट्रस्ट की गैर-कानूनी हस्तक्षेप मानते हैं। पुलिस किसके आदेश पर उस छापेमारी में शामिल हुई? उनका सवाल है कि रुपए बरामद होने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई? दरअसल हमारा भी यह मानना है कि पहली बरामदगी और 25 जून को प्राथमिकी दर्ज कराने के बीच 20 लंबे दिनों का फासला था। उस दौरान आरोपितों और उनके आकाओं ने सबूत मिटा दिए होंगे, चोरी की रकम ठिकाने लगा दी होगी और उसके बावजूद अयोध्या पुलिस ने आरोपितों को रिमांड पर नहीं लिया, तो जाहिर है कि जांच का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। क्या चंदा-चढ़ावा चोरी का इतना संवेदनशील, भ्रष्ट मामला बेनतीजा भी रह सकता है? साफ लगता है कि ट्रस्ट के स्तर पर बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, लिहाजा अपराध में बराबर की भूमिका चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा आदि की भी है! पुलिस ने चंपत राय से भी पूछताछ की है और उनका बयान दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और न ही उन्हें आरोपित करार दिया गया है। क्यों? आश्चर्य यह है कि पुलिस ने 8 आरोपितों के घर पर छापेमारी की। नकदी, आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जाने का दावा भी किया जा रहा है।

आरोपितों के परिजनों से भी पूछताछ की गई है। फिर भी अदालत में पुलिस ने आरोपितों की रिमांड क्यों नहीं मांगी? क्या पुलिस सब कुछ जानती है? क्या पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य जुटा लिए हैं? हमें तो राजनीतिक दबाव, आरोपितों को संरक्षण, सांठगांठ का मामला लगता है। बड़ी मछलियां डर रही होंगी कि ये छोटी मछलियां कहीं सच न उगल दें और मगरमच्छ जाल में न फंस जाएं! गौरतलब यह भी है कि प्रभु श्रीराम के मंदिर में व्यापक, अनवरत चोरी की जाती रही, उसकी जांच तो अभी जारी है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन का मुद्दा उछाल दिया है। उसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी लपेटने की कोशिश की गई है। क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा चंदा-चढ़ावा चोरी भी बन सकता है? जांच तो उन राम-शिलाओं की भी होनी चाहिए, जो चांदी की बनी थीं। साथ में दीपक और फूल भी चांदी के थे। देश के करीब 5 लाख गांवों में 100-100 रुपए की पर्ची काट कर धन इक्ा किया गया था। कहां है वह धन? कौन हिसाब देगा? इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और घपला करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह का घपला न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

बाल पुरस्कारों के लिए मप्र के बच्चों का आह्वान

भारत प्रतिभाओं की धरती है। यहां के गांवों, कस्बों और शहरों में ऐसे हजारों बच्चे हैं, जो अपनी उम्र से कहीं आगे बढ़कर समाज, पर्यावरण, विज्ञान, खेल, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। कोई कठिन परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखते हुए वैज्ञानिक सोच के साथ नवाचार कर रहा है, कोई जल और जंगल बचाने का अभियान चला रहा है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में नाम रोशन कर रहा है, तो कोई अपनी संवेदनशीलता और साहस से समाज के लिए मिसाल बन रहा है। स्वरभाविक है इस कार्य को मध्य प्रदेश के हमारे अपने अनेकों बच्चीं भी कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य यह है कि इनमें से अनेक बच्चों की प्रेरक कहानियां स्थानीय स्तर तक ही सीमित रह जाती हैं।

वास्तशव में ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश के बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों से ह्लप्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारह्व के लिए अधिक से अधिक नामांकन भेजने का आह्वान किया गया है। यह पुरस्कार उस सोच का सम्मान है, जो यह सिद्ध करती है कि परिवर्तन लाने के लिए बड़ी उम्र नहीं, बड़ा संकल्प चाहिए। यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो तो छोटी उम्र में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जोकि पांच से 18 वर्ष आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने असाधारण धैर्य, साहस, सृजनात्मकता और अदम्य जज्बे का परिचय दिया हो। प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति इन प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करते हैं। पुरस्कार छह श्रेणियों, जिसमें कि बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शामिल हैं, मेंप्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर किया जाता है।

यह दिवस दसवें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान और नैतिक साहस की स्मृतियों को याद करने के लिए है। मात्र नौ और सात वर्ष की आयु में अपने सिद्धांतों और आस्था से समझौता न करने वाले इन वीर बालकों का जीवन आज भी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उसी अमर परंपरा को वर्तमान पीढ़ी की उपलब्धियों से जोड़ने का माध्यम है, जहां साहस, सेवा, समर्पण और उत्कृष्टता को राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है।

वर्ष 2019 में इस पुरस्कार की नई व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक देशभर के 203 बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है। इन बच्चों की उपलब्धियां विविध क्षेत्रों में रही हैं। किसी ने बाढ़ या आग जैसी आपदा में लोगों की जान बचाई, किसी ने वैज्ञानिक उपकरण विकसित किए, किसी ने दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी तकनीक बनाई, किसी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए हजारों लोगों को जागरूक किया, तो किसी ने खेल या कला के क्षेत्र में भारत का गौरव बढ़ाया। इन प्रेरक कहानियों ने यह साबित किया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर, संसाधन या आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती। मध्य प्रदेश में भी ऐसी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। जनजाति अंचलों से लेकर नगर, महानगरों तक अनेक बच्चे अपनी मेहनत और रचनात्मकता से नई पहचान बना रहे हैं। अलग-अलग दिशा में हमारे बच्चे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब ऐसे बच्चों के कार्यों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आवश्यक है कि समय रहते उनका नामांकन किया जाए।

अब जिन छह श्रेणियों में यह पुरस्का र दिया जाता है, उनमें अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों की सहायता की हो या संकट की घड़ी में अद्वितीय साहस और सूझबूझ का परिचय दिया हो, उसे बहादुरी के अंतर्गत सम्मोन ये सम्मांन मिलता है। समाज सेवा श्रेणी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों या समुदाय के हित में प्रेरणादायी कार्य किए हों। पर्यावरण श्रेणी में प्रकृति संरक्षण, जैव विविधता, जल संरक्षण, स्वच्छता और जलवायु संबंधी प्रयासों को महत्व दिया जाता है। खेल श्रेणी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए है। कला एवं संस्कृति में संगीत, नृत्य, चित्रकला, लोककला, रंगमंच और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्रेणी में ऐसे नवाचारों को मान्यता दी जाती है, जिनसे समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान हुआ हो या लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली हो। इस पुरस्कार की सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी योग्य बच्चे का नामांकन उसके माता-पिता, शिक्षक, सामाजिक संस्था, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन या कोई भी जिम्मेदार नागरिक कर सकता है। इतना ही नहीं, यदि कोई बच्चा स्वयं को पात्र मानता है, तो वह स्व-नामांकन भी कर सकता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि किसी प्रतिभाशाली बच्चे की उपलब्धि सिर्फ जानकारी के अभाव में छूटना नहीं चाहिए।

पात्रता की दृष्टि से आवेदक भारतीय नागरिक और भारत का निवासी होना चाहिए। 31 जुलाई 2026 को उसकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उपलब्धि या कार्य पिछले दो वर्षों के भीतर का होना चाहिए। आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज, हाल का फोटो तथा उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण नामांकन की अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन पोर्टल https://awards.gov.in पर जमा करना होगा।

यहां यह भी समझें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वास्तीव में उस विश्वास का प्रतीक है कि राष्ट्र अपने बच्चों की प्रतिभा, संवेदनशीलता, साहस और नवाचार को देख रहा है, समझ रहा है और उसका सम्मान कर रहा है। यह सम्मान उन बच्चों को नई पहचान देता है और लाखों अन्य बच्चों को यह संदेश देता है कि सकारात्मक सोच, निरंतर मेहनत और समाज के प्रति जिम्मेदारी किसी भी उम्र में राष्ट्रीय गौरव का कारण बन सकती है।

मध्य प्रदेश के बच्चोंव के लिए यह अवसर प्रदेश की नई पीढ़ी की प्रतिभा को देश के सामने प्रस्तुत करने का भी है। यदि आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी उम्र से कहीं बड़ा कार्य किया है, तो उसकी कहानी राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का समय यही है। याद रखिए; एक सही समय पर किया गया नामांकन किसी बच्चे के जीवन की दिशा बदल सकता है और उसे देशभर के बच्चों के लिए प्रेरणा बना सकता है। संभव है, इस वर्ष राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होने वाले असाधारण बच्चों में मध्य प्रदेश के भी हमारे कई होनहार बालक या बालिका भी शामिल हों, बस आवश्यकता है उनकी प्रतिभा को पहचानने और समय पर आगे लाने की, जो कार्य आप सभी को अपने आस-पास के बच्चोंम की प्रतिभा को ध्या न में रखकर करना है।

(लेखक - डॉ. निवेदिता शर्मा)
(लेखक मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं)

मयार्दा के मंदिर में पारदर्शिता की घंटी कब बजेगी?

राम भारतीय मानस में केवल एक नाम नहीं, बल्कि मयार्दा का पर्याय हैं। इसलिए जब उनके नाम से जुड़ी किसी संस्था, ट्रस्ट या व्यवस्था पर वित्तीय अनियमितताओं, कथित गबन या अपारदर्शिता के आरोपों की चर्चा होती है, तब चोट केवल कानून को नहीं लगती है। यह घाव समाज की आत्मा पर पड़ता है। ईंट-पत्थर से बने मंदिरों की मरम्मत संभव है, लेकिन टूटे हुए विश्वास का पुनर्निर्माण सबसे कठिन कार्य है। इतना ही नहीं विडंबना यह है कि इस देश में धर्म की रक्षा के नाम पर अक्सर धर्म के मूल तत्व सत्य, ईमानदारी और उत्तरदायित्व को ही सबसे पहले किनारे रख दिया जाता है। प्रश्न पूछने वाले को संदेह की निगाह से देखा जाता है, जबकि हिसाब देने वाले से कोई प्रश्न नहीं किया जाता। मानो श्रद्धा का अर्थ विवेक का परित्याग हो। यह वही समाज है जो दान-पात्र में नोट डालते समय आँखें बंद कर लेता है और बाद में खुलासों पर आँखें मलता रह जाता है।

कबीर ने लिखा था कि, ह्लराम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट ह्व उनका आशय भक्ति की उस अमूल्य संपदा से था जिसे हर कोई बिना मूल्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन समय ने इस पंक्ति का ऐसा विडंबनापूर्ण रूप गढ़ दिया है कि अब कई बार यह प्रश्न उठने लगता है। क्या कहीं ह्लरामह्व साधना का नहीं, साधन का नाम बनते जा रहे हैं? क्या आस्था की छाया में जवाबदेही का सूर्य अस्त हो जाता है? ऐसे में यदि राम मंदिर या उससे जुड़े किसी ट्रस्ट के संदर्भ में वित्तीय गड़बड़ियों या कथित गबन की बातें सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनती हैं, तो सबसे पहली अपेक्षा निष्पक्ष जांच और पूर्ण पारदर्शिता की होनी चाहिए। जो संस्था स्वयं को नैतिक आदर्शों का प्रतिनिधि मानती है, उसे सामान्य संस्थाओं से कहीं अधिक कठोर सार्वजनिक परीक्षण स्वीकार करना चाहिए। यदि सब कुछ सही है तो जांच से प्रतिष्ठा बढ़ेगी; यदि नहीं, तो सुधार का मार्ग खुलेगा। दोनों ही स्थितियों में सत्य का लाभ होगा। सबसे बड़ा व्यंग्य यह है कि भगवान राम ने राजपाट त्यागकर मयार्दा बचाई थी, लेकिन आज कहीं-कहीं मयार्दा को त्यागकर प्रतिष्ठान बचाने की बेचैनी दिखाई देती है। राम ने न्याय के लिए अपने निजी सुखों का बलिदान दिया था, जबकि आधुनिक समय में कुछ

लोग न्याय से बचने के लिए राम के नाम का सहारा खोजते दिखाई देते हैं। यह विरोधाभास केवल हास्यास्पद नहीं, गहरी नैतिक विफलता का संकेत है। समाज का एक हिस्सा हर आरोप को बिना जांच अंतिम सत्य मान लेता है और दूसरा हर आरोप को बिना जांच षड्यंत्र कहकर खारिज कर देता है। दोनों प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक चेतना को कमजोर करती हैं। न अंधविश्वास स्वस्थ है, न अंध-अविश्वास। आवश्यकता तथ्यों, स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक जवाबदेही की है। कानून और नैतिकता दोनों का सम्मान तभी संभव है जब भावनाएँ प्रमाणों का स्थान न ले लें। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार से भी अधिक चयनात्मक नैतिकता है। यदि आरोप किसी विरोधी पर हों तो हम न्याय की माँग करते हैं, और यदि वही प्रश्न अपने प्रिय पक्ष पर उठे तो उसे आस्था पर हमला घोषित कर देते हैं। सिद्धांतों का मूल्य तभी है जब वे व्यक्ति, दल, विचारधारा और संस्था से ऊपर खड़े रह सकें। अन्यथा नैतिकता केवल भाषणों की सजावट बनकर रह जाती है।

राम का नाम किसी आर्थिक लेन-देन की ढाल नहीं बन सकता। वह तो स्वयं सत्य की कसौटी है। यदि किसी ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं के विश्वास और दान का दुरुपयोग किया हो, तो वह केवल वित्तीय अपराध नहीं बल्कि नैतिक विश्वासघात भी होगा। और यदि आरोप असत्य हों, तो उन्हें तथ्यों और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खारिज किया जाना चाहिए, न कि भावनात्मक नारों के सहारे। यह भी विचारणीय है कि मंदिर की भव्यता केवल शिखर की ऊँचाई से नहीं मापी जाती। उसकी वास्तविक ऊँचाई उसके लेखे-जोखे की ईमानदारी, प्रशासन की पारदर्शिता और प्रबंधन की जवाबदेही से तय होती है। संगमरमर की चमक उस समय फीकी पड़ जाती है जब हिसाब की किताब धुंधली दिखाई देने लगे। राम भारतीय संस्कृति में इसलिए पूजनीय नहीं हैं कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने शक्ति पर मयार्दा को वरीयता दी। यदि आज उनके नाम पर बनी किसी भी व्यवस्था में मयार्दा की जगह अपारदर्शिता, सत्य की जगह प्रचार और जवाबदेही की जगह मौन ले ले, तो सबसे बड़ा अपमान राम का नहीं होगा। सबसे बड़ा अपमान उन मूल्यों का होगा जिनके कारण राम युगों-युगों तक आदर्श बने रहे। समय की माँग स्पष्ट है: श्रद्धा बनी रहे, किंतु उसके साथ साहस भी जुड़ा रहे; मंदिर खड़े रहें, लेकिन उनके साथ सत्य भी खड़ा रहे; दान आता रहे और उसके साथ सार्वजनिक लेखा-परीक्षा भी चलती रहे। क्योंकि अंतत: राम की सबसे बड़ी पूजा दीप जलाने में नहीं, सार्वजनिक जीवन को मयार्दा, ईमानदारी और सत्य के प्रकाश से आलोकित करने में है।

(लेखिका - सोनम लववंशी)
(स्वतंत्र लेखिका एवं शोधार्थी)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

मिलावट के मकडजाल में फंसा भारतीय उपभोक्ता

प्रख्यात लेखक आर्थर कोएस्टलर ने अपनी किताब में भारतीय व्यापारियों के बारे में लिखा था, ह्यउनमें से कुछ इतने लालची तथा पत्थर दिल हैं कि खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने से जरा भी संकोच नहीं करते। चाय में कीकर की खुश्क पत्तियां, हल्दी में पीला रंग तथा चीनी में मैदा मिलाना उनका नित्य नियम बन गया है। यही कारण है कि बहुत से यूरोपीय, भारत की चाय पर चीन या श्रीलंका की चाय को अधिमान देते हैं।

भोजन पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी की मूलभूत आवश्यकता है। भारत में स्वस्थ भोजन का अधिकार सभी का मौलिक अधिकार है। नागरिकों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना राज्य तथा केन्द्र सरकार का कर्तव्य है। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने का अधिकार नहीं होना चाहिए और इसके परिणाम उसको भुगतने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा था, ह्यकि जो भी उत्पाद बनाओ उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने का संकल्प लें ह्न इसके विपरीत हमारे देश में जीवन रक्षक दवाइयों के नमूने फेल हो रहे हैं, सब्जियां और फल जहरीले रसायनों से सने हैं, पानी दूषित है, खाने की वस्तुओं में मिलावट का धंधा जोरों पर है जिससे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित मिलावट की कुछ घटनाओं का उल्लेख जरूरी है। 22 मई 2026 को हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला और काला अंब में बनी दवाइयों के 31 नमूने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा चैक करने पर फेल पाए गए हैं।

पहले भी हिमाचल के दवाई उद्योगों में बनी दवाइयां गुणवत्ता पर ठीक नहीं उतरी थीं। यहां की एक कंपनी की बनी कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत हो गई थी। देश में अन्य जगहों पर बनने वाली दवाइयां भी गुणवत्ता के चैक पर फेल हो रही हैं। पहले भी भारत के अन्य राज्यों में निर्मित कफ सिरप के सेवन से इंडोनेशिया, गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बहुत से बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। 22 मार्च 2026 तक राजमहेंद्रवरम (आंध्र प्रदेश) जिले के कोरुकोंडा मंडल के नरसपुरम गांव में स्थित वरलक्ष्मी मिल्क डेयरी के संदिग्ध रूप से मिलावटी दूध पीने के कारण मरने वालों की संख्या 16 हो गई थी। इस दूध में एथिलीन ग्लाइकोल नामक जहरीला रसायन मिला होने के कारण मौतें हुई थी। यह रसायन कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। एक जनवरी 2026 को हैदराबाद में नव वर्ष की पार्टी में एक्सपायर्ड मसालों से बनाया खाना खाने के बाद एक व्यक्ति की मौत और 14 अन्य बीमार हो गए थे। पटियाला (पंजाब) में रेड़ के दौरान पाया कि महंगी शराब की बोतलों में घटिया शराब भरकर बाजार में बेची जा रही थी। देश की कई जगहों से जहरीली शराब पीने से मरने वालों की खबरें तो आती ही रहती हैं। यह उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी है और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। अगर आप किसी भी अस्पताल का दौरा करें तो वहां आपको विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलेंगी। अगर खाद्य पदार्थों में मिलावट इसी तरह चलती रही तो ये कतारें बढ़ती ही रहेंगी। डाक्टर मरीज को स्वस्थ जीवन जीने के लिए फल और सब्जियों के सेवन की सलाह देते हैं, परंतु फल-सब्जियां पैदा करने से लेकर पकने तक जहरीले रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। कीटनाशकों के अवैज्ञानिक और अंधाधुंध इस्तेमाल से फल और सब्जियों के साथ-साथ भूमिगत जल भी दूषित हो रहा है जिससे लोग कैंसर, लिवर, किडनी की गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यह गंभीर चिंतन का विषय है। खाद्य पदार्थों में मिलावट आजकल एक गंभीर समस्या बन गई है। मिलावट का अर्थ है किसी भी ऐसे पदार्थ को मिलाना जिससे खरीददार संतुष्ट न हो या पदार्थ की गुणवत्ता खराब हो जाए। कोई भी वस्तु तभी शुद्ध मानी जाती है जब वह खाद्य सुरक्षा एवं सेवा प्राधिकरण के मानकों के तहत बनाई गई हों। कुछ लोग चंद पैसों की खातिर दूध, पनीर, खोया, अदरक-लहसुन, पेस्ट, मसाले, व्रत के आटे, काली मिर्च, हल्दी, नारियल तेल, शहद तथा मंदिरों में वितरित होने वाले प्रसाद आदि में मिलावट कर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फल, अनाज, सब्जी और दूध का उत्पादन बहुत बढ़ा है, परन्तु कीटनाशकों और जहरीले रसायनों के इस्तेमाल से सब्जियों और फलों के अलावा पर्यावरण और पीने का पानी भी दूषित हो रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। सेबों पर एक ही सीजन में 10-12 बार स्प्रे किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर से मरने की दर 9.5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 7.7 प्रतिशत है। हिमाचल में कैंसर केसों की वार्षिक ग्रोथ दर 2.2 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय दर 0.6 प्रतिशत है। अस्पतालों में डाक्टर एंटीबॉयोटिक्स पर ही जोर दे रहे हैं, जो कि रोगी के लिए लंबे समय के लिए ठीक नहीं हैं। प्रधानमन्त्री ने दिसंबर 2025 को मन की बात में जनता से अपील की थी कि डाक्टर की सलाह के बगैर एंटीबॉयोटिक्स का सेवन न करें। डाक्टर को भी अति आवश्यक हो तो ही एंटीबॉयोटिक्स प्रिस्क्राइब करनी चाहिए क्योंकि रोगाणुरोधी प्रतिरोध भारत की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है। परिणामस्वरूप सामान्य संक्रमणों का इलाज भी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। सरकार को दवाइयों के रेट निर्धारित कर दवाई निमार्ताओं तथा विक्रेताओं का लाभ कम करके उपभोक्ताओं का शोषण रोकना चाहिए। जेनेरिक दवाइयों की गुणवत्ता को बरकरार रखकर इनके ज्यादा उपयोग पर बल देकर हर अस्पताल में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र खोलकर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करनी चाहिए। पैकेजिंग प्रोडक्ट के लेबलिंग पर वर्णित प्रोडक्ट के घटकों के लिए मजबूत नियामक ढांचा होना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण को समय-समय पर आडिट और रैंडम टेस्टिंग कर, उल्लंघन के लिए जुमार्ना करना चाहिए। जिस देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बाजार में बहुतायत हो और कानूनों का सख्ती से पालन न हो, उस देश के नागरिक स्वास्थ्य की दृष्टि और आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर होंगे, क्योंकि वे अस्पताल और दवाइयों के चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित कानूनों और जांच की वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में जागरूकता जरूरी है।

सत्यपाल वशिष्ठ, स्वतंत्र लेखक

आलेख

संतुलित कूटनीति से उभरता भारत का वैश्विक नेतृत्व

भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संतुलित, स्वतंत्र और दूरदर्शी सोच रही है। विश्व राजनीति के बदलते परिदृश्य, महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक अस्थिरताओं के दौर में भारत ने जिस परिपक्वता और विवेक का परिचय दिया है, उसने उसे विश्व मंच पर एक विश्वसनीय, जिम्मेदार और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के उपरांत उनके अंतिम संस्कार में भारत की ओर से उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का निर्णय भी इसी संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति का परिचायक है। यह केवल एक राजनयिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक, सभ्यतागत एवं रणनीतिक संबंधों के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा तथा बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का तेहरान जाना यह स्पष्ट करता है कि भारत अपने मित्र देशों के साथ संबंधों को केवल सामरिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के आधार पर भी देखता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि उनके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, किंतु भारत की गरिमापूर्ण उपस्थिति ने यह संदेश अवश्य दिया कि भारत अपने मित्र देशों के सुख-दु:ख में सहभागी बनने की परंपरा का निर्वाह करता है।

वास्तव में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की रही है। आज भारत के अमेरिका, रूस, इजरायल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोप, जापान और आसियान देशों के साथ मजबूत रणनीतिक एवं आर्थिक संबंध हैं। दूसरी ओर ईरान के साथ भी उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ऊर्जा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष के साथ अत्यधिक निकटता दूसरे पक्ष के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकती है। किंतु भारत ने सदैव यह सिद्ध किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है। ईरान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर भारत की प्रतिक्रिया भी अत्यंत संतुलित रही। भारत ने ईरानी दूतावास जाकर शोक संवेदना व्यक्त की, किंतु किसी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय आरोप-प्रत्यारोप में स्वयं को शामिल नहीं किया। भारत ने न तो अमेरिका की आलोचना की और न ही इजरायल के विरुद्ध कोई आक्रामक टिप्पणी की। यह वही कूटनीतिक परिपक्वता है, जिसने भारत को वैश्विक राजनीति में एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का मूल आधार ह्यराष्ट्रहित सर्वोपरिह्न रहा है। इसी कारण भारत ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय दबाव के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है।

रूस-यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि वह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक था। साथ ही भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत बनाए रखा। यह संतुलन साधना आसान नहीं था, किंतु भारत ने इसे सफलतापूर्वक निभाया। यही कारण है कि आज भारत को किसी गुट विशेष का सदस्य नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र वैशिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। भारत और ईरान के संबंध हजारों वर्षों पुराने हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, भाषाई, साहित्यिक और व्यापारिक संबंधों का समृद्ध इतिहास रहा है। फारसी भाषा और संस्कृति का भारतीय सभ्यता पर गहरा प्रभाव रहा है। मुगल काल से लेकर आधुनिक युग तक दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान निरंतर चलता रहा है। आर्थिक दृष्टि से भी ईरान भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारत लंबे समय तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति ईरान से करता रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को कुछ समय के लिए ईरान से तेल आयात रोकना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के संबंधों में कोई स्थायी कटुता नहीं आई।

चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत और ईरान के रणनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यह परियोजना भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करती है तथा पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार के नए अवसर उपलब्ध कराती है। ऐसे समय में जब चीन ह्यबेल्ट एंड रोडह्न परियोजना के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है, चाबहार भारत के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने पिछले एक दशक में अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। भारत ने अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग विकसित किया है। इजरायल के साथ कृषि, रक्षा और नवाचार के क्षेत्र में नई साझेदारियां स्थापित हुई हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। रूस के साथ परंपरागत मित्रता को भी भारत ने मजबूती प्रदान की है। यही नहीं, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ भी भारत ने अपने संबंधों को नई दिशा दी है।

जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस कुशलता और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया, उसने विश्व समुदाय को प्रभावित किया। ह्यवसुधैव कुटुम्बकम्ह्न की भावना के साथ भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को मुखर किया। अफ्रीकी संघ को जी-20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की भूमिका ऐतिहासिक रही। इससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत केवल अपने हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विकासशील देशों की आकांक्षाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी पड़ोसी नीति भी है। भारत ने सदैव ह्यपड़ोसी प्रथमह्न की नीति को अपनाया है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद भी भारत ने वहां की जनता को मानवीय सहायता उपलब्ध कराई। भारत ने अनाज, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री भेजकर यह संदेश दिया कि उसका संबंध केवल सरकारों से नहीं, बल्कि वहां की जनता से भी है। कोविड-19 महामारी के दौरान ह्यवैक्सीन मैत्रीह्न अभियान के माध्यम से भारत ने अनेक देशों को टीके उपलब्ध कराए। श्रीलंका जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब भारत ने उसे खाद्यान्न, ईंधन, दवाइयां और आर्थिक सहायता प्रदान की। नेपाल, भूटान, मालदीव और बांग्लादेश को भी भारत ने समय-समय पर हरसंभव सहयोग दिया है। यही कारण है कि भारत आज क्षेत्रीय स्थिरता और विकास का प्रमुख आधार बनकर उभरा है।

इसके विपरीत, पाकिस्तान लंबे समय से भारत विरोधी दुष्प्रचार और षड्यंत्रों की नीति अपनाता रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न तनावों तथा हिंसक घटनाओं के लिए भी पाकिस्तान समय-समय पर भारत को दोषी ठहराने का प्रयास करता रहा है। यह उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है, जिसके माध्यम से वह अपने आंतरिक संकटों और असफलताओं से ध्यान हटाना चाहता है। वास्तविकता यह है कि भारत ने सदैव क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और विकास का समर्थन किया है। भारत ने कभी भी किसी पड़ोसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति नहीं अपनाई। इसके विपरीत, उसने मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। पाकिस्तान के निराधार आरोपों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत को एक जिम्मेदार और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में देखता है। आतंकवाद के विरुद्ध भारत की स्पष्ट नीति और शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। यही कारण है कि आज विश्व के अधिकांश देश भारत को स्थिरता, विकास और सहयोग के एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।

आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति, जनसांख्यिकीय क्षमता और कूटनीतिक सक्रियता ने भारत को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में ला खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सक्रिय विदेश यात्राओं और विश्व नेताओं के साथ निरंतर संवाद ने भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ किया है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह शक्ति और संवेदना, दोनों को साथ लेकर चल रहा है। वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए मानवता, सहयोग और वैशिक कल्याण की भावना को भी महत्व देता है। ईरान के साथ संबंधों को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाने का निर्णय इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। आज की जटिल विश्व व्यवस्था में वही राष्ट्र सफल हो सकता है, जो संवाद, संतुलन, सह-अस्तित्व और दूरदर्शिता का परिचय दे। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह न केवल अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि विश्व शांति, स्थिरता और सहयोग का भी एक विश्वसनीय वाहक बन सकता है। निस्संदेह भारत की संतुलित विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कूटनीतिक प्रयास आने वाले वर्षों में भारत को एक सशक्त, प्रभावशाली और नैतिक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

(लेखक - ललित गर्ग)
(लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

मुख्यमंत्री ने जेपीसी सदस्यों से की मुलाकात

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में वन नेशन, वन इलेक्शन से जुड़े दो संशोधन विधेयकों पर अध्ययन के लिए आए संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। यह समिति संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के विभिन्न प्रावधानों पर राज्यों एवं अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए दिल्ली आई है।

मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों का दिल्ली सचिवालय में स्वागत करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुशासित एवं प्रशासनिक रूप से दक्ष बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से सुझाव प्राप्त करने की यह पहल अत्यंत सराहनीय है। दिल्ली सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरी गंभीरता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समिति को अपने विस्तृत सुझाव भी उपलब्ध कराएगी।

समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सांसद विष्णु दयाल राम, भर्तृहरि महताब, डॉ. संबित पात्रा, विष्णुदत्त शर्मा, सुखदेव भगत, जीएम हरीश बालयोगी, के राधाकृष्णन, घनश्याम तिवारी, कविता पाटीदार और संजय जयसवाल उपस्थित रहे।

शिक्षा व्यवस्था सहित अनेक सार्वजनिक सेवाएँ होती हैं प्रभावित

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव होना समय की आवश्यकता है। इससे बेहतर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। पूरे देश में अगर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों तो देश की ऊर्जा, समय और संसाधनों की बड़ी बचत होगी। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण प्रशासनिक व्यवस्था लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहती है। आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकारी मशीनरी का बड़ा हिस्सा चुनावी दायित्वों में लग जाता है। विशेष रूप से दिल्ली जैसे छोटे राज्य में चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगने से शिक्षा व्यवस्था सहित अनेक सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होती हैं।

बैठक के दौरान समिति ने दोनों संशोधित विधेयकों से जुड़े संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक पहलुओं पर मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। चर्चा में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनावों का समन्वय, चुनावी चक्र का एकीकरण, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम पर संभावित प्रभाव, प्रशासनिक तैयारियों इत्यादि सहित अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकारों का कार्यकाल भी प्रभावित होता है। राष्ट्रहित में एक ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए जिससे सरकारें बिना अनावश्यक व्यवधान के पूरे मनोयोग से जनता के विकास के लिए कार्य कर सकें।

दिल्ली के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी का चुनावी कार्यक्रम लोकसभा चुनाव से लगभग एक वर्ष के अंतर पर होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली के कार्यकाल में आवश्यक समायोजन करना पड़े तो दिल्ली सरकार सकारात्मक सोच के साथ इस पर विचार करने को तैयार है। अगर राष्ट्रहित में आवश्यकता हो तो दिल्ली इस दिशा में सहयोग करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देश का ऐसा महानगर है जहां लगभग सभी राज्यों के नागरिक निवास करते हैं। इसलिए चुनावी व्यवहार और मतदान से जुड़े अनेक विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भी यहां विशेष महत्व रखता है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति द्वारा मांगे गए सभी विषयों पर दिल्ली सरकार औपचारिक रूप से विस्तृत अध्ययन कर अपने लिखित सुझाव भी प्रस्तुत करेगी।

संक्षिप्त वार्ता

उपराज्यपाल ने कमिश्नरेट दिवस परेड की ली सलामी

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट दिवस के मौके पर परेड की सलामी ली। ये परेड किंग्सवे कैंप स्थित 'न्यू पुलिस लाइंस ग्राउंड' में हुई। उन्होंने पुलिस बल से अपील की कि वे मानवीय, ईमानदार और टेक्नोलॉजी पर आधारित पुलिसिंग' के मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं।

उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस बल की अटूट प्रतिबद्धता, अनुशासन और व्यावसायिकता एक सुरक्षित, संरक्षित और नागरिक-केंद्रित राष्ट्रीय राजधानी की आधारशिला बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सेवा और समर्पण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम एक सुरक्षित दिल्ली की परिकल्पना की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं।

ढाई साल में राम मंदिर क्यों नहीं गए गृह मंत्री अमित शाह?

नई दिल्ली, वेब वार्ता। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे की बड़े पैमाने पर हुई चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर बनने के बाद पिछले ढाई साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी राम मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने नहीं गए। केजरीवाल ने दावा किया कि आज के समय में आम आदमी पार्टी ही देश की 'असली सनातनी पार्टी' है।

दिल्ली को मिली 8.1 किलोमीटर लंबी द्वारका सुरंग की सौगात, मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, वेब वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राजधानी दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही 6 लेन वाली द्वारका सुरंग परियोजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 8.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग के निर्माण पर 6969.67 करोड़ रुपये की लागत आएगी। परियोजना को मिश्रित व्यवस्था के तहत अगले 5 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सुरंग द्वारका द्रुतमार्ग के शिव मूर्ति चौराहे को दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। इसके बनने से पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा तथा गुरुग्राम, द्वारका, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

नीट-परास्नातक परीक्षा पर सेना चिकित्सकों को राहत नहीं

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो सेना चिकित्सकों को नीट-परास्नातक 2026 परीक्षा में आवेदन करने और शामिल होने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि नियमों की वैधता पर अंतिम निर्णय से पहले अंतरिम राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा और न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने सशस्त्र बल अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि केवल नियमों को चुनौती दिए जाने के आधार पर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

उच्च न्यायालय ने सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सांसद राघव चड्ढा को निशाना बनाने वाली कुछ आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को हटाने का आदेश दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए चड्ढा ने इससे पूर्व कथित तौर पर दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत सोशल मीडिया पोस्ट के प्रकाशन के खिलाफ उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने कहा था कि ये पोस्ट उनकी प्रतिष्ठा और उनके व्यक्तित्व के अधिकारों के लिए बेहद नुकसानदेह थीं।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले में अंतरिम आदेश सुनाते हुए कहा, मैंने कहा कि इसमें व्यक्तित्व के अधिकार का मामला नहीं है। हालांकि, मैंने उन्हें (कुछ सामग्री को) हटाने के लिए कहा है। न्यायाधीश ने कहा, वैसे सामग्री प्रथम दृष्टया मानहानिकारक नहीं है। आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है। अदालत ने कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए अंतरिम राहत के पहलू पर फैसला 21 मई को सुरक्षित रख लिया था। चड्ढा ने अपनी याचिका में सोशल मीडिया मंच पर बड़े पैमाने पर प्रसारित की जा रही गलत, एआई निर्मित और डीपफेक सामग्री को तुरंत हटाने का अनुरोध किया था।उनके मुकदमे में यह दलील दी गई थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डीपफेक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अनधिकृत रूप से छेड़छाड़ कर सामग्री तैयार की गई थी और इसे प्रसारित किया जा रहा था, जो चड्ढा के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान जैसी कई मशहूर हस्तियों, द्यआर्ट ऑफ लिविंगद्ध के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी, पॉडकास्टर राज शमानी और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी इससे पूर्व अपने व्यक्तित्व और प्रचार से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत दी थी।

श्याम लाल कॉलेज में क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल समर स्कूल का हुआ आयोजन

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के श्याम लाल कॉलेज में 'क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी: हैंड्स-ऑन एक्सप्लोरेशन एंड इमर्जिंग फ्रंटियर्स' विषय पर 10-दिवसीय नेशनल समर स्कूल सफलतापूर्वक बुधवार को संपन्न हुआ। इसमें पूरे देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह कार्यक्रम युवा शिक्षार्थियों के बीच वैज्ञानिक उत्कृष्टता, नवाचार और अनुसंधान-उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा देने के कॉलेज के संकल्प को दर्शाता है।

उत्तम नगर में विजय सेल्स शोरूम में भीषण आग, करोड़ों का सामान राख

नई दिल्ली, वेब वार्ता। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में बुधवार तड़के विजय सेल्स के चार मंजिला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल विभाग ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

दमकल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र अटवाल के अनुसार, बुधवार सुबह करीब 4.15 बजे सूचना मिली कि

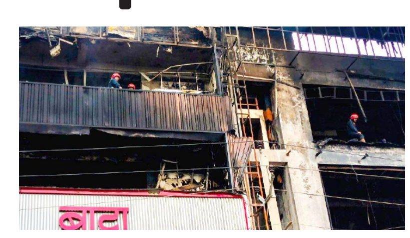

उत्तम नगर में मेट्रो पिलर संख्या-663 के पास स्थित विजय सेल्स के शोरूम में आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की नौ गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। आग तेजी से फैलती देख इसे मेक-6 घोषित किया गया और अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया। स्थानीय पुलिस, पीसीआर और एंबुलेंस भी मौके पर पहुंच गईं।

करीब 350 गज में बने इस शोरूम में बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपर तीन मंजिलें हैं। शोरूम का विस्तार करने के लिए साथ वाली इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल को भी विजय सेल्स में शामिल किया गया था, जिसका रास्ता मुख्य इमारत से बनाया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आग तीसरी मंजिल से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। दमकल कर्मियों ने समय रहते आग को आसपास की दुकानों और इमारतों तक फैलने से रोक लिया। विजय सेल्स के साथ स्थित बाटा के शोरूम तक आग नहीं पहुंचने दी गई, हालांकि उसके ऊपर की वे मंजिलें, जिन्हें विजय सेल्स उपयोग कर रहा था, पूरी तरह जल गईं।

जनसमस्याओं के समाधान के लिए विधायक ने अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली, वेब वार्ता

त्रिलोकपुरी के विधायक रविकांत ने बुधवार को अपने जनसेवक विधायक कार्यालय में क्षेत्र के नागरिकों एवं परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को जनसमस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

रविकांत ने कहा कि जनसेवा उनके लिए केवल दायित्व नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान, मूलभूत सुविधाओं का विस्तार और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

...यही हमारा कर्तव्य

उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना उनका लक्ष्य एवं संकल्प है। विधायक ने आश्वस्त किया कि जनहित से जुड़े कार्यों के लिए उनका कार्यालय सदैव नागरिकों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि ₹जनता की सेवा, जनता के साथ – यही हमारा संकल्प, यही हमारा कर्तव्य।

जेपी पब्लिक स्कूल में रंगमंच कार्यशाला का शुभारंभ

जेपी पब्लिक स्कूल, नोएडा में भारत सरकार के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज तथा विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 'शिक्षा में रंगमंच' विषय पर एक माह की विशेष कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला 30 जुलाई तक आयोजित की जाएगी।

नोएडा, (वेब वार्ता)

कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच, संप्रेषण कौशल तथा टीम भावना का विकास रंगमंच के माध्यम से करना है। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अभिनय, वाचन, शारीरिक अभिव्यक्ति, स्वर के प्रभावी प्रयोग, तात्कालिक अभिनय, नाट्य खेल तथा मंचीय प्रस्तुति की विभिन्न विधाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कार्यशाला में प्रशिक्षण की जिम्मेदारीसुनील चौहान निभा रहे हैं। इसका संचालन अंजली मलिक के मार्गदर्शन तथा डॉ. मुकेश उपाध्याय के संरक्षण में किया जा रहा है। कार्यक्रम का निर्देशन सुदेश शर्मा कर रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, अभिव्यक्ति क्षमता और नेतृत्व कौशल को नई दिशा मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2026 अधिसूचित की

नई दिल्ली, 01 जुलाई (वेब वार्ता)

दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2026 को अधिसूचित कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि यह नीति एक जुलाई से प्रभावी हो गई है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इससे पहले इस नीति को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने मंजूरी दी थी।

अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में एक स्वच्छ, आधुनिक और प्रदूषण मुक्त परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नई नीति का उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति को तेज करना है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, इसका लक्ष्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना, ईंधन पर निर्भरता को कम करना, चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार करना और एक मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र विकसित करना है। गुप्ता ने कहा कि इस नीति में वित्तीय प्रोत्साहन, डिजिटल पारदर्शिता, संस्थागत निगरानी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर समान रूप से जोर दिया गया है।

जनकपुरी में इलेक्ट्रॉनिक सामान के बहुमंजिला शोरूम में आग लगी; लाखों का सामान जलकर खाक हुआ

दिल्ली के जनकपुरी स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक बहुमंजिला शोरूम में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई और लाखों रुपये मूल्य का सामान जलकर नष्ट हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

नई दिल्ली, 01 जुलाई (वेब वार्ता)

दिल्ली दमकल सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तम नगर-नजफगढ़ रोड पर स्थित विजय सेल्स के शोरूम में तड़के 4.15 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में बहुमंजिला इमारत से उठतीं आग की लपटें और आसमान में घना काला धुआं नजर आ रहा है, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता था।

पुलिस ने बताया कि आग पास के बाटा शोरूम तक भी फैल गई जिसके बाद अधिकारियों ने इलाके को सुरक्षित किया और दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुट गए। डीएफएस अधिकारी ने बताया कि दमकलकर्मियों ने शुरू में दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर भेजीं लेकिन जैसे ही आग ने भीषण रूप लिया तो दमकल की और गाड़ियां सेवा में लगाई गईं। आग पर सुबह करीब 6:30 बजे काबू पा लिया गया।

आग बुझने के बाद भी दमकलकर्मियों को ऊपरी मंजिलों पर तेज दबाव वाले पानी की बौछारें करते देखा गया ताकि आग को पूरी तरह से बुझाया जा सके तथा उसे और फैलने से रोका जा सके। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर शीतलन अभियान जारी है। आग ने इमारत के भूतल, प्रथम तल और तीन ऊपरी मंजिलों में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान, फर्नीचर और अन्य चीजों को अपनी चपेट में ले लिया। यह इमारत करीब 350 वर्ग गज में फैली है।

डीएफएस अधिकारी ने कहा, नुकसान के स्तर का आकलन किया जा रहा है लेकिन माना जा रहा है कि आग में लाखों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गई है। उन्होंने कहा कि आग लगने का कारण अभी ज्ञात नहीं है।

सर्दियों में प्रदूषण पर सख्ती, सरकार ने बनाई नई व्यवस्था

नई दिल्ली, वेब वार्ता। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी कार्ययोजना अधिसूचित कर दी है। इसके तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक विशेष नियम लागू रहेंगे, जबकि बिना वैध प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पूरे वर्ष ईंधन नहीं दिया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों से घर से कार्य कराने की व्यवस्था लागू की जाएगी।

स्मार्ट बच्चे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने शिक्षकों को किया प्रशिक्षित

वेब वार्ता, अब्दुल रशीद

नई दिल्ली। राजधानी के स्कूलों को बच्चों के लिए और अधिक सुरक्षित एवं बाल-मित्र बनाने की दिशा में दिल्ली पुलिस ने ह्यस्मार्ट बच्चे अभियानद्ध के तहत मास्टर ट्रेनर्स के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम, बाल सुरक्षा, स्कूल सुरक्षा तथा साइबर जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता को मजबूत बनाना तथा उन्हें बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं के प्रति जागरूक करना था, ताकि वे अपने-अपने विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकें। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शिक्षकों को पॉक्सो अधिनियम

के विभिन्न प्रावधानों, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की पहचान, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और पीड़ित बच्चों के प्रति

संवेदनशील व्यवहार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों की सतर्कता और संवेदनशीलता बच्चों को अपराधों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा स्कूल सुरक्षा के विषय पर भी विशेष चर्चा की गई। शिक्षकों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा अभिभावकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के उपाय बताए गए। साइबर जागरूकता सत्र के दौरान इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के बीच बच्चों के सामने आने वाले खतरों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षकों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी प्रोफाइल, डिजिटल शोषण और अन्य साइबर अपराधों की पहचान एवं रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने पर भी बल दिया गया।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों को सशक्त बनाकर ही स्कूलों को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील और बाल-अनुकूल बनाया जा सकता है। मास्टर ट्रेनर्स अपने विद्यालयों में अन्य शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षित करेंगे, जिससे यह जागरूकता अभियान और व्यापक रूप से प्रभावी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बच्चे अभियानका उद्देश्य बच्चों को केवल अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तौर-तरीकों के प्रति भी जागरूक बनाना है।

संक्षिप्त वार्ता

14 साल तक अंकपत्र रोकने पर कॉलेज प्रबंधन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थायी लोक अदालत ने छात्रा का अंकपत्र 14 वर्षों तक रोककर रखने के मामले में सलेमपुर स्थित रैनाथ ब्रह्मदेव पीजी कालेज के प्रबंधक, प्राचार्य और वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने तीनों को संयुक्त रूप से 20 लाख रुपये प्रतिकर के रूप में छात्रा को अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा 10 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है।

अधिकाधिक प्रवक्ता के अनुसार जिले के रैनाथ ब्रह्मदेव पीजी कालेज की छात्रा सरिता देवी ने वर्ष 2011-12 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कालेज प्रबंधन ने अंक सुधार के नाम पर उनका मूल अंकपत्र अपने पास जमा करा लिया। इसके बाद सरिता देवी ने कई बार अंकपत्र वापस करने की मांग की, लेकिन कालेज प्रशासन ने उसे उपलब्ध नहीं कराया।

पोषण समिति की बैठक में डीएम ने परखी योजनाओं की प्रगति

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाल विकास विभाग के अंतर्गत गठित पोषण समिति की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने अधूरे आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीडीपीओ, सुपरवाइजर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को टीम भावना से कार्य करते हुए विभागीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीडीपीओ प्रभावी अनुश्रवण करें तथा सुपरवाइजर भी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी कार्यकताओं को उनके दायित्वों के प्रति प्रेरित करें और कार्यों की नियमित निगरानी करें। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के आयोजित सत्रों में जिन क्षेत्रों में मातृ अथवा शिशु मृत्यु हुई हो अथवा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र संघर्षशील श्रेणी में हो, वहां सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर सभी गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराएं।

कुशीनगर में तैयार हुआ भव्य बुद्ध थीम पार्क, आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान

11.32 करोड़ रुपए की लागत से बना बुद्ध थीम पार्क, जल्द खुलेगा पर्यटकों के लिए

वेब वार्ता, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर उत्तर प्रदेश की पहचान को और मजबूत करने वाली एक बड़ी परियोजना अब साकार हो चुकी है। कुशीनगर में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) के द्वारा गौतम बुद्ध संग्रहालय के निकट लगभग 11.32 करोड़ रुपये की लागत से विकसित बुद्ध थीम पार्क पूरी तरह तैयार हो गया है और जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। आधुनिक तकनीक, आध्यात्मिक अनुभव और बौद्ध विरासत के अनूठे संगम के रूप में विकसित यह पार्क तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को भगवान बुद्ध के जीवन, दर्शन और करुणा के संदेश से जोड़ने का नया माध्यम बनेगा।

यह थीम पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि बौद्ध ज्ञान और आध्यात्मिकता का जीवंत अनुभव केंद्र होगा। यहां इंटरएक्टिव स्टोरीटेलिंग, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन और आधुनिक प्रस्तुतीकरण तकनीकों के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं और शिक्षाओं को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पार्क का उद्देश्य आगंतुकों को केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें आत्मचिंतन और आंतरिक जागृति का अनुभव कराना भी है।

पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण बोधि वृक्ष होगा, जो संवादात्मक शैली में बुद्ध के ज्ञान, करुणा और जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा तिब्बती शैली के स्तूप, प्रार्थना चक्र (प्रेयर व्हील्स), मूर्तिकला स्थापनाएं और विभिन्न अनुभवात्मक प्रदर्शनियां आगंतुकों को बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से रूबरू कराएंगी। यहां स्थापित आठ तथागत स्तूप भगवान बुद्ध के आठ महान कार्यों का प्रतीक होंगे और बौद्ध दर्शन की गहराई को समझने का अवसर प्रदान करेंगे।

पार्क में तैयार की गई 3ऊ झांकियां और डिजिटल प्रदर्शनियां भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत करेंगी। वहीं विशेष रूप से विकसित ट्रेवलॉग इंस्टॉलेशन बुद्ध की पवित्र यात्रा को चरणबद्ध तरीके से दर्शाएगा। इसके अतिरिक्त भूमिस्पर्श, ध्यान, अभय और धर्मचक्र सहित बुद्ध की आठ विशाल मुद्राएं स्थापित की गई हैं, जो उनके जीवन, उपदेशों और बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पार्क में अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल तकनीक का भी उपयोग किया गया है। यहां 40 फीट ऊंची फैसाड बुद्ध वॉल पर भव्य लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा। जिसमें कला, तकनीक और कहानी कहने की शैली के माध्यम से भगवान बुद्ध के जीवन और उनके संदेशों को प्रस्तुत किया जाएगा। यह शो पार्क के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा और आगंतुकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करेगा।

पार्क का भव्य प्रवेश द्वार भी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। प्राचीन बौद्ध तोरणों से प्रेरित इस प्रवेश द्वार पर उत्कृष्ट नक्काशी और प्रतीकात्मक कलाकृतियां उकेरी गई हैं, जो शांति, ज्ञान और करुणा के संदेश को दर्शाती हैं। इसके साथ ही पार्क में बुद्ध जीवन दीघाएं, बुद्ध के जीवन प्रसंगों पर आधारित कलात्मक भित्ति चित्र, सांस्कृतिक थीम पर आधारित बच्चों का खेल क्षेत्र तथा स्मारिका केंद्र भी विकसित किया गया है, जहां बौद्ध हस्तशिल्प और स्थानीय कारीगरों के उत्पाद उपलब्ध होंगे।

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह के हवाले से जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि, बुद्ध थीम पार्क का निर्माण पूरा होना कुशीनगर में बौद्ध पर्यटन को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

हरदोई के लाल यश दयाल गुप्ता ने गोवा में लहराया विजय पताका

इंटरनेशनल ताइक्वांडो एशिया कप में जीता स्वर्ण पदक

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। प्रतिभा जब अथक परिश्रम, अनुशासन और अटूट आत्मविश्वास का हाथ थाम लेती है, तब सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। हरदोई जनपद के सांडी नगर के होनहार खिलाड़ी यश दयाल गुप्ता ने इसी सत्य को चरितार्थ करते हुए गोवा में आयोजित 9वीं ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो एशिया कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे हरदोई, उत्तर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है।

90 किलोग्राम भार वर्ग में उतरे यश ने पूरे टूनार्मेंट के दौरान अद्भुत आत्मविश्वास, तकनीकी कौशल और जुझारूपन का परिचय दिया। फाइनल मुकाबले में उनका सामना पंजाब के खिलाड़ी रचित से हुआ। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में यश ने अपने दमदार खेल से प्रतिद्वंद्वी को परास्त करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया और तिरंगे का मान विश्व पटल पर ऊंचा कर दिया।

सांडी नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं समाजसेवी विमल गुप्ता के पुत्र यश दयाल गुप्ता बचपन से ही खेलों के प्रति समर्पित रहे हैं। कठिन अभ्यास, दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत के बल पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह स्वर्णिम सफलता उनकी वर्षों की साधना और संघर्ष का प्रतिफल है। ताइक्वांडो के अलावा यश ने बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और निशानेबाजी (शूटिंग) जैसे खेलों में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देकर यह साबित किया है कि लगन और मेहनत के बल पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है।

यश दयाल गुप्ता की यह सफलता केवल एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि हरदोई की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का संदेश है कि दृढ़ निश्चय, अनुशासन और निरंतर परिश्रम से असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य भी सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। उनकी यह स्वर्णिम विजय आने वाले खिलाड़ियों के लिए नई ऊर्जा और नई उम्मीद का स्रोत बनेगी।

हासिल करते रहेंगे गौरवपूर्ण उपलब्धियाँ

यश की इस शानदार उपलब्धि की सूचना जैसे ही हरदोई पहुंची, पूरे जनपद, विशेषकर सांडी नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर शुभचिंतकों, खेल प्रेमियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का तांता लग गया। सभी ने यश को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की और विश्वास व्यक्त किया कि वे आने वाले समय में भी इसी प्रकार देश के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे।

कुशीनगर पुलिस में बड़ा फेरबदल: 26 इंस्पेक्टर-दारोगा के तबादले

एसपी ने जनहित में किए ट्रांसफर, साइबर थाने से महिला सेल तक बदले प्रभारी

वेब वार्ता, कुशीनगर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक ने जनहित व प्रशासनिक हित में 26 निरीक्षक व उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। रविवार 29 जून 2026 को जारी प्रेस नोट के अनुसार कई थानों के प्रभारियों समेत महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती बदली गई है। साइबर थाना, एएचटीयू, महिला थाना और कई थानाध्यक्ष बदले गए हैं।

प्रमुख तबादले एक नजर में निरीक्षक विद्याधर कुशवाहा : प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू से प्रभारी वीआईपी सेल, निरीक्षक जितेन्द्र टण्डन : प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना से प्रभारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/मिशन शक्ति, निरीक्षक चन्द्रभूषण प्रजापति : प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया से प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू, निरीक्षक संजय दूबे : प्रभारी निरीक्षक हाटा से प्रभारी निरीक्षक नेबुआ नौरंगिया, निरीक्षक विनय कुमार सिंह : प्रभारी निरीक्षक सेवरही से प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना, म0निरी0 सुमन सिंह: प्र0नि0 महिला थाना से पुलिस लाइन गैर जनपद स्थानांतरण , उ0नि0 धीरेन्द्र राय: थानाध्यक्ष पटहेरवा से थानाध्यक्ष कप्तानगंज, उ0नि0 दीपक सिंह: थानाध्यक्ष कप्तानगंज से थानाध्यक्ष हाटा , उ0नि0 इत्यनन्द पाण्डेय: थाना कसया से थानाध्यक्ष कसया, म0उ0नि0 चन्दा यादव: थाना कोतवाली पडरौना से थानाध्यक्ष महिला थाना पडरौना भेजा गया है। इसके अलावा कई उप निरीक्षकों को चौकी, सेल और थानों में नई तैनाती दी गई है। राजेश यादव को कसया से पडरौना, अश्वनी सिंह को कुबेरस्थान, जयप्रकाश यादव को सेवरही भेजा गया है।

एसपी कार्यालय से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। विभाग में लंबे समय से तबादलों की चर्चा थी। इस फेरबदल को कानून-व्यवस्था मजबूत करने की कवायद माना जा रहा है।

बिजली गिरने से 4 झुलसे

देवरिया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बैतालपुर क्षेत्र में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से चार लोग झुलस गए। इनमें पिता-पुत्र भी शामिल हैं। झुलसे व्यक्तियों को स्थानीय लोगों ने देवरिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया। जहाँ पर चिकित्सकों ने एक को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार जिले के नगर पंचायत बैतालपुर के वार्ड संख्या-9 आनंद नगर के किसान मंगलवार सुबह खेतों में धान की रोपाई कर रहे थे। अचानक तेज बारिश शुरू होने पर वे पास के एक मुर्गी फार्म के शेड में शरण लेने पहुंचे। इस फार्म पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी।

हरदोई में विशेष संचारी एवं दस्तक अभियान का आगाज, एक माह तक चलेगा जनजागरूकता अभियान

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को विशेष संचारी एवं दस्तक अभियान का शुभारम्भ नयागांव मुबारकपुर स्थित 100 शैय्या चिकित्सालय से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती ने फीता काटकर किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से स्वच्छता अपनाने, घरों और आसपास जलभराव न होने देने तथा बुखार होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल में जांच कराने की अपील की।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. भवनाथ पाण्डेय ने बताया कि विशेष संचारी अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा, जबकि दस्तक अभियान 11 जुलाई से शुरू होगा। इसमें स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, नगर विकास, पंचायतीराज, शिक्षा, कृषि, पशुपालन समेत सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकताओं की टीमें घर-घर जाकर लोगों को संचारी रोगों से बचाव, मच्छरों की रोकथाम तथा हाथ धोने के सही तरीके की जानकारी देंगी। साथ ही खांसी, जुकाम, बुखार, फाइलेरिया, कुष्ठ, टीबी के संभावित मरीजों और कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ा जाएगा। टीमें घरों में मच्छरों के पनपने वाले स्थानों की भी पहचान कर उनका निस्तारण कराएंगी।

कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविन्द सचान, अभियान के नोडल अधिकारी एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुरेन्द्र कुमार, 100 शैय्या चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. सी.बी. सिंह, डॉ. राजेश सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सीडीओ नेहा डब्याल ने ली समीक्षा बैठक

अभियान के सफल संचालन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी नेहा डब्याल की अध्यक्षता में विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में विशेष संचारी अभियान की द्वितीय अंतरविभागीय बैठक भी आयोजित हुई। सीडीओ ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत सौंपे गए कार्य पूरी गंभीरता और समयबद्ध ढंग से किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक गतिविधि की फोटो निर्धारित ग्रुप पर साझा करने के निर्देश दिए ताकि अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अभियान से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

गैसड़ी बी-पैक्स को प्रदेश में प्रथम स्थान, लखनऊ में हुआ सम्मान

वेब वार्ता, कमर खान

गैसड़ी / बलरामपुर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार को बी पैक्स गैसड़ी को आनलाइन सदस्य बनाने में राज्य में प्रथम स्थान पाये जाने पर सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं अध्यक्ष रामदीन वर्मा को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है।

गैसड़ी बी पैक्स के सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता, प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ल, राज्य मंत्री सहकारिता जेपीएस राठौर द्वारा गैसड़ी बी पैक्स द्वारा वित्तीय वर्ष 2025/26 सदस्यता यहां अभियान में 2323आन लाइन सदस्य बनाये जाने पर प्रदेश में प्रथम स्थान पाये जाने पर सम्मान एवं पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया गया है। इसके लिए अतिथियों द्वारा किसानों के हित में उत्कृष्ट कार्य करने की सराहना करते हुए शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन की प्रशंसा की गई है।

बी पैक्स अध्यक्ष राम दीन शमार्ने बताया कि इस सम्मान को पाकर शासन द्वारा लिए जा जा रहे निर्णयों का अनुपालन करने के लिए मनोबल बढ़ा है। किसानों के हित में बी पैक्स सहकारी समिति गैसड़ी के कर्मचारी बेहतर कार्य करेंगे। गैसड़ी बी पैक्स समिति को सम्मानित किये जाने पर सहायक आयुक्त/ सहायक निबंधक सहकारिता अजय कुमार मौर्य,एडीओ सहकारिता अनूप कुमार श्रीवास्तव सचिव जमुनी राघवेन्द्र प्रताप सिंह, सचिव श्री प्रकाश सिंह, कर्मचारी जगराम मौर्य, राम बाबू, दयाराम, राम बेचन समेत अन्य कर्मचारियों ने हर्ष व्यक्त किया है।

स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का आगाज

डीएम ने दिखाई जागरूकता रैली को हरी झंडी

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। जिले में शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य के साथ बुधवार को स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने कम्पोजिट विद्यालय, सिविल लाइन से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रथम चरण में नामांकन से वंचित रहे प्रत्येक बच्चे का विद्यालय में प्रवेश हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए।

डीएम ने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इसके लिए शिक्षक और विभागीय अधिकारी घर-घर जाकर अभिभावकों को जागरूक करें तथा बच्चों का नामांकन कराएं।

अभियान के दौरान कोई भी पात्र बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए।

शैक्षिक सत्र 2026-27 के तहत एक जुलाई से शुरू हुए अभियान के दूसरे चरण में निकाली गई जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने और समय पर नामांकन कराने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रत्नेष कुमार ने जिलाधिकारी सहित अतिथियों का पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। संचालन कमलेश ने किया। इस अवसर पर जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) प्रदीप श्रीवास्तव, खंड शिक्षा अधिकारी नीतू वर्मा एवं गौरव शुक्ला सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

देहदान संकल्प महोत्सव में 30 देहदानियो ने देहदान का लिया संकल्प

कानपुर। युग दधीनि देहदान संस्थान के बैनर तले आयोजित समारोह में बुधवार को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के एल टी थ्री हॉल अद्भुत क्षणों का साक्षी बना।वेदपाठी बटुकों के मंत्रोच्चार से हाथों में पान, सुपारी, अक्षत, पुष्प एवं गंगाजल लिये गंगापीठाधीश्वर प0 रामजी त्रिपाठी उनकी पत्नी श्रीमती साधना अभियान की प्रेरणा स्त्रोत रहीं स्वतंत्रतासेनानी ले0 मानवती आयार्जी के पुत्र दिनेश एवं बहू सुरभि आर्या सहित तीस देहदानियों ने "अहं देहदानम् संकल्पम्करोमि" कहते हुये अपनी देह राष्ट्र हित समर्पित करने का संकल्प लिया।

सीडीओ के औचक निरीक्षण में स्कूल-आंगनबाड़ी की खुली पोल

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई, 1 जुलाई। जिले में सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं की हकीकत बुधवार को उस समय सामने आ गई, जब मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) श्रीमती नेहा ब्याडवाल ने विकास खंड बावन के उच्च प्राथमिक विद्यालय भिठारी एवं आंगनबाड़ी केंद्र भिठारी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में छात्र-छात्राओं की कम उपस्थिति, शिक्षकों की अनुपस्थिति, गंदगी, अव्यवस्थाएं और आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में गंभीर लापरवाही मिलने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कई जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय में पंजीकृत 121 छात्र-छात्राओं के सापेक्ष केवल 60 विद्यार्थी उपस्थित मिले। चार स्वीकृत शिक्षकों में से सिर्फ एक शिक्षक मौजूद था, जबकि तीन शिक्षक अवकाश पर थे। विद्यालय परिसर में साफ-सफाई की स्थिति भी बेहद खराब मिली। जगह-जगह घास-फूस और मलबा पड़ा था। इतना ही नहीं, पर्याप्त बेंच उपलब्ध होने के बावजूद कक्षा छह के बच्चों को दरी पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा था।

इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापक अजय कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने तथा खंड शिक्षा अधिकारी बावन को शिथिल पर्यवेक्षण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए। साथ ही विद्यालय की क्षतिग्रस्त बाल पेंटिंग एवं एस्ट्रोनॉमी लैब की पेंटिंग का तत्काल रंग-रोगन कराने के निर्देश जिला पंचायत राज अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव को दिए।

इसके बाद सीडीओ ने विद्यालय परिसर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भिठारी का निरीक्षण किया। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रजौली देवी अनुपस्थित मिलीं, जबकि 45 पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष केवल दो बच्चे ही मौजूद थे। केंद्र की बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर नीलू कश्यप तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए।

सीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छात्र उपस्थिति बढ़ाने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परियोजना निदेशक डीआरडीए अशोक कुमार, अधिशासी अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण विभाग) प्रदीप पाल, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया उपाध्याय तथा खंड विकास अधिकारी बावन डॉ. राम प्रकाश भी मौजूद रहे।

यदि इसे दैनिक जागरण, अमर उजाला या हिन्दुस्तान जैसी क्राइम/सिटी पेज की अखबारी भाषा में और धारदार बनाना चाहें, तो उसे भी तैयार किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण ख़बर

कांग्रेस के कद्दावर नेता का निधन, राजनीतिक जगत में शोक की लहर

■ ढाका। चीन में कटहल की मांग बढ़ती जा रही है। भारत-बांग्लादेश श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के स्थानीय बाजार में बिकने वाला कटहल अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बन गया है। वियतनाम से बड़े पैमाने पर कटहल आयात करने के बाद अब चीन बांग्लादेश से बड़ा करार करने जा रहा है। इससे कटहल एक बार भी कृषि व्यापार की चर्चा के केंद्र में आ गया है।

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान हाल ही में चीन यात्रा पर गए थे। यहां दोनों देशों के बीच कृषि व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष तौर पर अगर किसी चीज पर बात हुई तो वह कटहल और चीनी ही थी। फिलहाल चीन की ओर से प्रस्ताव दिया गया और गुणवत्ता मानकों को सेट किया जा रहा है, जिसका साफ संकेत है कि बांग्लादेश को चीन कटहल के बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर देख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश दुनिया के प्रमुख कटहल उत्पादक देशों में शामिल है।

राजनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस

■ नई दिल्ली। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों के शहीद होने के संबंध में सदन को गुमराह किया। वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से आग्रह किया कि सदन को गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने नोटिस में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई, 2025 को हुई चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इसके विपरीत बाद में जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के छह जवानों की मृत्यु हुई थी।

रिकॉर्ड: भारत ने जमकर किया रूसी कच्चे तेल का आयात

जून के रिकॉर्ड में छू सकता है नई ऊंचाइयां

समझौतों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को दिया है नया रूप

यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और व्यापार समझौतों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को नया रूप दिया है, जिसके चलते रूस भारत का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने रियायती रूसी कच्चे तेल की खरीद में लगातार वृद्धि की है, जिससे उन्हें ऊर्जा लागत को नियंत्रित करने और रिफाइनिंग मार्जिन को बढ़ाने में मदद मिली है। रियायती दरों पर रूसी तेल की उपलब्धता भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।

नई दिल्ली। भारत में रूसी कच्चे तेल का आयात जून में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है, जैसा कि एनर्जी एक्सपर्ट ने दावा किया है। उन्होंने बताया कि भारतीय बंदरगाहों पर रूसी कच्चे तेल से लदे टैंकरों की इतनी बड़ी संख्या पहले कभी नहीं देखी गई। एनजीपी एनर्जी कैपिटल मैनेजमेंट के अर्थशास्त्री ने अपने बयान में कहा, जैसा कि मैंने जून की शुरूआत में कहा था, अगर इस महीने रूस से भारत का कच्चा तेल आयात रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने केप्लर का एक नक्शा भी साझा किया, जिसमें कई टैंकर रूसी कच्चे तेल को भारत भर के बंदरगाहों तक ले जाते हुए दिखाए गए थे।

भारत ने मई में अनुमानित 6.7 अरब डॉलर मूल्य के रूसी हाइड्रोकार्बन का आयात किया। इस महीने के दौरान रूस से भारत के आयात में कच्चे तेल का हिस्सा लगभग 83 प्रतिशत था, जिसकी कीमत 48 अरब यूरो थी। तेल उत्पादों और कोयले के आयात की कीमत क्रमशः 550 मिलियन यूरो और 429 मिलियन यूरो थी। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि रूस से कच्चे तेल की खरीद में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी के कारण मई में भारत के कुल कच्चे तेल के आयात की मात्रा में महीने दर महीने 8 प्रतिशत की तेजी आई है।भारत के कुछ सबसे बड़े रिफाइनिंग सेंटर्स ने रूसी तेल की आवक में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। गुजरात के वडीनार रिफाइनरी में उतारे गए तेल की मात्रा अप्रैल के स्तर से 36 प्रतिशत बढ़ी, जबकि जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में आपूर्ति 14 प्रतिशत बढ़ी। सरकारी स्वामित्व वाली रिफाइनरियों ने भी इस साल की शुरूआत में आयात फिर से शुरू करने के बाद खरीद बढ़ा दी। मई में न्यू मैंगलोर रिफाइनरी को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति पिछले महीने की तुलना में 13 प्रतिशत बढ़ी, जबकि विशाखापत्तनम रिफाइनरी में आयात में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओडिशा की पारादीप रिफाइनरी ने दो सालों में रूसी तेल की मात्रा में दोगुनी बढ़ोतरी दर्ज की है।

बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट चीन को सौंपा

भारत को सतर्क रहने की जरुरत

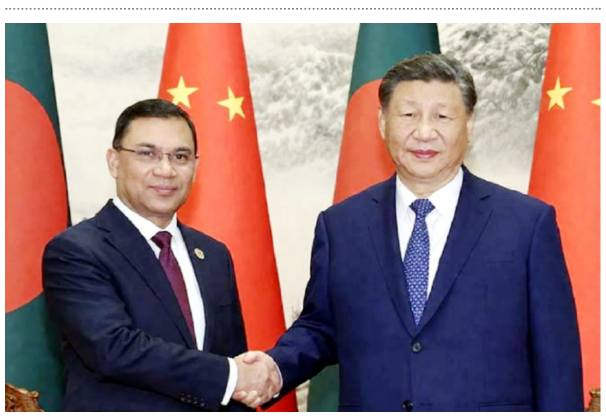

नई दिल्ली। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की हालिया चीन यात्रा और उनके विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के बयान को देखें तो यह भारत के लिए सतर्क रहने का समय है। मोहम्मद यूनुस ने दोनों देशों के रिश्ते को अबतक के सबसे निचले स्तर पर ला दिया था। चुनाव के बाद तारिक रहमान सत्ता में आए तो लगा कि शायद पहले वाली स्थिति में कुछ बदलाव होगा, लेकिन चीन को लेकर बांग्लादेश जो रवैया अपना रहा है, वह भारत के लिए सही नहीं है।

मोहम्मद यूनुस की तरह तारिक रहमान का मंसूबा कितना खतरनाक?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वहां के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से पूछ लिया कि पीएम तारिक रहमान की चीन यात्रा में बांग्लादेश को क्या मिला। इसपर खलीलुर तमतमा गए। उन्होंने कहा कि आपने कैश में फायदे की बात की। इस तरह के सवाल मत पूछिए..। हमें बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है। वे पीएम रहमान दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्ते की दिशा तय करने के लिए गए। उन्होंने आगे कहा कि थोड़ा आत्म-सम्मान जरूरी है। हम अब अलग स्तर पर पहुंच चुके हैं। इसपर यकीन करिए। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी मीडिया को भरोसा दिलाने के लिए वह बात भी कह दी, जो भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक नजरिए से खतरे की घंटी से कम नहीं है।

अजम्पशन आईलैंड में भारत के मिलिट्री बेस बनाने पर फिर चर्चा शुरू

यह भारत और सेशेल्स के बीच एक संयुक्त प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। पीएम नरेन्द्र मोदी के सेशेल्स दौरे में अजम्पशन आईलैंड में भारत के मिलिट्री बेस बनाने पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से इस द्वीप में भारत के नेवल बेस बनाने को लेकर सवाल पूछा था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सेशेल्स की सरकार इस बारे में बात करती है तो हम उस पर चर्चा करने को तैयार हैं।

भारतीय विदेश सचिव के बयान के बाद साफ है कि हिंद महासागर में भारत अपनी रणनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। सेशेल्स के अजम्पशन आइलैंड पर भारतीय नौसैनिक बेस या कोस्टगार्ड फैसिलिटी को लेकर चचाएं एक बार फिर गर्म हैं। विक्रम मिस्री ने साफ किया है कि भारत इस परियोजना के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय विदेश सचिव ने साफ किया हमारा साफ रुख है कि कोई भी प्रोजेक्ट सेशेल्स सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाएगा।

मार्च 2024 में एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सेशेल्स के राष्ट्रपति ने माना है कि भारत सेशेल्स के साथ समुद्री और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। सेशेल्स सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का पहला नौसेना बेस बनाने के लिए अजम्पशन आइलैंड पर जमीन का एक टुकड़ा आवंटित किया है। इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट से जुड़ी गोपनीयता को हटाते हुए सेशेल्स के राष्ट्रपति जेम्स मिशेल ने उस सयम बताया था कि यह भारत और सेशेल्स के बीच एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पश्चिमी तट पर आपसी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे दोनों देशों की रक्षा सेनाएं शामिल हैं। सेशेल्स इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भारत ने सेशेल्स की चिंताओं को दूर करते हुए 2018 में एक नया समझौता किया था। इसमें साफ किया गया कि यह सेशेल्स की सेना की संपत्ति होगी लेकिन भारत की नौसेना और वायुसेना को इसका इस्तेमाल करने की छूट होगी। चीन ने जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा बनाया है। अजम्पशन आइलैंड पर पकड़ होने से भारत पश्चिमी हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रख सकता है। यह आइलैंड मोजाम्बिक चैनल के बेहद करीब है जहां से दुनिया के बड़े तेल टैंकर और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं।

बता दें भारत ने पहले ही सेशेल्स में तटीय निगरानी रडार नेटवर्क स्थापित किया है जिससे इस प्रोजेक्ट को जोड़ने पर भारत को पूरे रीजन की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानि समुद्री खुफिया जानकारी मिलती रहेगी। यह प्रोजेक्ट पिछले कुछ समय से ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन अब भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया है कि भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह खुला है। उन्होंने साफ कहा कि अगर सेशेल्स सरकार इस मुद्दे को उठाती है या इसकी जरूरत समझती है तो भारत उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने के लिए तैयार है।

देश में सक्रिय मॉनसून

कई राज्यों में भारी बारिश अरुणाचल में भूस्खलन से तबाही

नई दिल्ली। देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 1 जुलाई, बुधवार को कई राज्यों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इस बीच, अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। 14 गांवों के 3,100 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। नारी-कोयू क्षेत्र में धान के खेतों, कृषि भूमि, निजी संपत्ति और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। तबिरीपो साकू, लोग्लू, रोटे, रामे और कोयू सहित कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है, जिससे लगभग 500 परिवार अलग-थलग पड़ गए हैं। कई वाहन और पशु बाढ़ में बह गए, और दो मकान जलकर नष्ट हो गए। बिजली, पेयजल और संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जिला प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवक राहत व सड़क बहाली अभियान में जुटे हैं, और प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक, बिजली गिरने और

40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है।

पूर्वी और मध्य भारत में भी मॉनसून

पूर्वी और मध्य भारत में भी मॉनसून का प्रभाव तेज रहेगा। बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की संभावना है, जहां लोगों को बिजली गिरने और तेज हवाओं से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर भारत में भी मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भारी बारिश की आशंका है।पश्चिमी भारत की बात करें तो गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र-कच्छ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है। गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा से जलभराव और यातायात बाधित होने की संभावना है।

दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में व्यापक वर्षा जारी रहेगी। केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने मछुआरों, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों और निचले इलाकों के निवासियों को मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

उप्र में बारिश की रफ्तार बढ़ी

उत्तर प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से बारिश की रफ्तार बढ़ी है, पिछले 24 घंटों में बरेली में सर्वाधिक 157 मिमी वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों में मॉनसून प्रदेश के शेष हिस्सों में भी सक्रिय हो जाएगा। जुलाई के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान है कि देशभर में कुल वर्षा सामान्य से कम रह सकती है, हालांकि उत्तर-पश्चिम, पूर्व-मध्य और पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं।

कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने लगेगा आर्कटिक क्षेत्र: शोध

जूनो। हाल ही गहरे अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक क्षेत्र की जमी हुई बर्फ के नीचे छिपा विशाल कार्बन भंडार आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती को और गंभीर बना सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो वर्तमान में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला आर्कटिक क्षेत्र वर्ष 2050 के आसपास इस भूमिका को खो सकता है और इसके बजाय बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करने लगेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि ऐसा हुआ तो वैश्विक तापमान वृद्धि की रफ्तार तेज हो सकती है। अब तक जलवायु मॉडल यह मानकर चलते रहे थे कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और उसके आसपास की भूमि लंबे समय तक कार्बन को अवशोषित करती रहेगी। बढ़ते तापमान के कारण बर्फ पिघलने के बावजूद वहां वनस्पतियों की वृद्धि अधिक कार्बन सोखने में मदद करेगी। इसी आधार पर अनुमान लगाया गया था कि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कुछ हद तक संतुलित करता रहेगा।

खड़ी ट्रॉली से भिड़ी बस में लगी आग

8 तीर्थयात्रियों की जिंदा जलकर मौत

जयपुर। राजस्थान के दौसा जिले में बुधवार सुबह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में आठ तीर्थयात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 21 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब ऋषिकेश से इंदौर जा रही एक टूरिस्ट बस मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग पर खड़ी एक खाली ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और बस देखते ही देखते धू-धूकर जलने लगी। बस में लगभग 37 तीर्थयात्री सवार थे, जिनमें से कई नींद में थे और उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तत्काल मौके पर पहुंचे। दौसा के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित स्वयं बचाव कार्य की निगरानी कर रहे थे। दमकल की टीमों को आग पर काबू पाने में करीब तीन घंटे का समय लगा, क्योंकि आग की लपटें काफी तेज थीं। जब तक आग बुझाई गई, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आग पर काबू पाने के बाद जले हुए शवों को बस से निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

दौसा:हादसे में 21 यात्री गंभीर हैं कुल 37 लोग सवार थे

प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण बस चालक को झपकी आना बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी आशंका जताई है कि बस की डिक्की में सिगरेट के बॉक्स रखे हुए थे, जिसके कारण आग और तेजी से फैली। हालांकि, इस बात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। दुर्घटनाग्रस्त बस हंस ट्रेवल्स की बताई जा रही है।

यह भीषण हादसा सुबह करीब 3 :30 बजे हुआ, जब अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। इस दुखद घटना ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा उपायों और रात की यात्रा के दौरान चालकों की सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सटीक कारणों तथा जिम्मेदार लोगों की पहचान के लिए विस्तृत जांच जारी है। इस दुर्घटना से तीर्थयात्रा पर निकले परिवारों में मातम छा गया है, और प्रशासन जल्द से जल्द जांच पूरी कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दे रहा है।

एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान ?

नई दिल्ली। आतंकवाद को लगातार पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं।

भारत ने अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की महत्वपूर्ण बैठक में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। नई दिल्ली इस बैठक में वीडियो और अन्य पुख्ता सबूत पेश करने वाली है, जिनसे स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि पाकिस्तान का आतंकी संगठनों को समर्थन लगातार जारी है। भारत के पास ऐसे कई निर्णायक सबूत हैं जो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। इनमें भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े वीडियो शामिल हैं, जिनमें मारे गए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और भारत इन्हें एफएटीएफ की अगली पूर्ण बैठक में एक बड़ा हथियार बनाएगा। इन वीडियो के अलावा, अन्य साक्ष्य भी यह सिद्ध करेंगे कि पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स यानी सरकारी अधिकारी और संस्थाएं स्वयं आतंकी संगठनों की सभाओं में सीधे तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस स्थित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग एफएटीएफ की इस आगामी बैठक में भारत का रुख बेहद आक्रामक रहने वाला है। नई दिल्ली की इस मुहिम को और मजबूती मिलेगी क्योंकि संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की यह कोशिश है कि एफएटीएफ पर पर्याप्त दबाव बनाया जाए ताकि पाकिस्तान को अपनी धरती पर सक्रिय नॉन-स्टेट एक्टर्स और आतंकी गतिविधियों के लिए अपने वित्तीय सिस्टम के इस्तेमाल पर जवाबदेह ठहराया जा सके।

अगर भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए इन ठोस सबूतों के आधार पर पाकिस्तान फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाता है, तो उसकी आर्थिक और राजनीतिक मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने सहित 34-सूत्रीय एक्शन प्लान लागू करने के दावों के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया था। ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाले देशों की एफएटीएफ द्वारा कड़ी निगरानी की जाती है और उनके सिस्टम की समय-समय पर समीक्षा होती है। ऐसे देशों को वैश्विक वित्तीय संस्थानों से फंड या कर्ज हासिल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो पहले से ही आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। पाकिस्तान लंबे समय से दुनिया भर में सनसनीखेज आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले जिहादी गुटों का घर होने के लिए बदनाम रहा है।

चीन को टक्कर देने की क्षमता रखता है भारत

वॉशिंगटन। भारत की तकनीकी क्षमता और इंजीनियरिंग प्रतिभा को लेकर अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उसने भारत को वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक असाधारण शक्ति के रूप में रेखांकित किया है। अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के अवर सचिव जैकब हेलबर्ग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इंजीनियरिंग वर्कफोर्स और टैलेंट के मामले में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चीन को वास्तविक चुनौती देने की क्षमता रखता है। यह बयान भारतीय प्रतिभा के विश्वव्यापी प्रभाव और स्वीकृति को दर्शाता है। वॉशिंगटन में आयोजित एक लीडरशिप समिट में हेलबर्ग ने भारत की विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा, तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी इकोसिस्टम

और मजबूत होती अर्थव्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से भविष्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक और अत्याधुनिक इनोवेशन के विकास में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हेलबर्ग के अनुसार, भारत का तकनीकी इकोसिस्टम तेजी से परिपक्व हो रहा है और विभिन्न तकनीकी प्रयोगों के विकास में देश उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

राष्ट्रीय दैनिक
टाइम्स ऑफ़ पीडिया

ताजा खबर

संक्षिप्त

मंत्री नेताम बोले: शिकायत पर प्रमुखता से कार्रवाई करेगा प्रशासन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को लेकर चल रही सियासी बहस के बीच कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम का बड़ा बयान सामने आया है। विपक्ष द्वारा नए कानून के लागू न होने और पुराने एक्ट के तहत स्नद्धक्र दर्ज किए जाने के आरोपों पर मंत्री ने साफ किया कि इस तरह की कोई शिकायत होगी, तो प्रशासन प्रमुखता से ध्यान देकर कार्रवाई करेगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि ये अच्छी बात है कि कांग्रेस धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के लिए चिंतित है। बहुत जल्दी लागू होगा। भाजपा की सरकार में अच्छे-अच्छे लोग कभी राम मंदिर का नाम नहीं लेते थे वे भी मंदिर जाना शुरू कर दिए। समय के अनुसार उनका परिवर्तित चेहरा दिखाई दे रहा है और उनके मुख से ऐसी बाते की जा रही ये समय का तकाजा है।

कालाबाजारी: दो विक्रय केंद्रों के लाइसेंस निलंबित

रायपुर। राज्य सरकार खरीफ सीजन 2026 के लिए किसानों को पर्याप्त रासायनिक खाद उपलब्ध कराने सतर्कता के साथ कार्य कर रही है। जिलों में भी खाद-बीज की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। खाद-बीज की कालाबाजारी को रोकने प्रशासन सतर्क है। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले में भी खरीफ 2026 के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य पर विक्रय रोकने के लिए व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि जिला कबीरधाम में सहकारी क्षेत्र में 57,200 मीट्रिक टन उर्वरक वितरण लक्ष्य के विरुद्ध सेवा सहकारी समितियों में 32,700 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जबकि डबल लॉक केंद्रों में 5,668 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध हैं। समितियों के माध्यम से किसानों को अब तक 21,151 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में 10,457 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जिसके विरुद्ध अब तक 7,639 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है। सहकारी समितियों एवं निजी विक्रय केंद्रों के माध्यम से उर्वरकों का वितरण निरंतर जारी है। डीएपी उर्वरक के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की अनुशंसाओं के अनुसार एनपीके, टीएसपी एवं एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और वितरण के संबंध में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। मैदानी अमलों द्वारा किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।

देवकीनंदन ठाकुर का श्रीमद भागवत 8 जुलाई से

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय वैश्य फेडेरेशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल प्रदेश महामंत्री एवं प्रवक्ता राजकुमार राठी एवं प्रदेश महामंत्री शिवरतन गुप्ता ने बताया की 8 से 14 जुलाई तक बुढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है । श्री अग्रवाल ने बताया कि कथा का प्रारंभ 8 जुलाई को प्रातः 9:00 बजे विशाल कलश यात्रा से होगा जो की पुरानी बस्ती स्थित महामाया मंदिर से प्रारंभ होकर सदानी चौक, बुढ़ापारा होते हुए इनडोर स्टेडियम पहुंचेगी।

रामगढ़ महोत्सव-2026: सीएम साय ने सीताबेंगरा गुफा का किया अवलोकन

कहा- हमारी सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ऐतिहासिक एवं रामवनगमन पर्यटन परिपथ से जुड़े रामगढ़ में आयोजित दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव-2026 के समापन समारोह में शामिल हुए. इस अवसर पर उन्होंने विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीताबेंगरा गुफा का अवलोकन किया और इसकी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं स्थापत्य विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की. मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही जोगीमारा गुफा के प्राचीन शिलालेख, भित्तिचित्रों तथा क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक धरोहर हाथीपोल का भी अवलोकन किया. इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि रामगढ़ सरगुजा की हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना, कला, आस्था और गौरवशाली इतिहास का जीवंत प्रतीक

है. उन्होंने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात यह स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य एवं पर्यटन का अद्भुत संगम है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती केवल प्राकृतिक संपदा से ही समृद्ध नहीं है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और पुरातात्विक विरासत भी विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान रखती है. रामगढ़ जैसी धरोहरें हमारी ऐतिहासिक अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव की अमूल्य निधि हैं, जिनका संरक्षण और संवर्धन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन और पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें और स्थानीय लोगों को भी रोजगार और आजीविका के नए अवसर प्राप्त हों.उल्लेखनीय है कि रामगढ़ पर्वत की पश्चिमी ढलान पर स्थित सीताबेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएँ भारतीय इतिहास, स्थापत्य, शिलालेख एवं चित्रकला की अनुपम धरोहर मानी जाती हैं. मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने इन्हीं पहाड़ियों में अपनी कालजयी कृति मेघदूत की रचना की थी, जिसका आरंभ 卐आषाढस्य प्रथमदिवसे卐 से होता है. इसी ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आषाढ़ के प्रथम दिवस पर रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है. लगभग 44 फीट लंबी सीताबेंगरा गुफा में निर्मित प्राकृतिक रंगमंच, जोगीमारा गुफा में तीसरी-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की भित्तिचित्र परंपरा तथा यहाँ प्राप्त प्राचीन अभिलेख इस क्षेत्र को विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं. रामगढ़ की एक अन्य महत्वपूर्ण पहचान हाथीपोल नामक प्राकृतिक सुरंग है.

सीएम बोले : खेल प्रतिभाओं को उपलब्ध कराएंगे आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन

156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव सहित समिति के सदस्यों ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए प्राप्त आवेदनों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया।

सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को अंतिम स्वरूप प्रदान किया। इनमें 20 अलग-अलग खेलों के खिलाड़ी शामिल हैं। इन्हें नौकरी देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। बैठक में अनुमोदित 156 खिलाड़ियों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ होगी।

राज्य के खिलाड़ी लंबे समय से इस सूची की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद खिलाड़ियों का यह इंतजार जल्द समाप्त

हो जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए पारदर्शी, समयबद्ध और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

चयनित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पात्रता के अनुरूप उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया और व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों का अनुभव और उपलब्धियां प्रदेश की नई खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, इसलिए उनकी सेवाओं का उपयोग खेल प्रशिक्षण, प्रतिभा संवर्धन और खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में भी किया जाना चाहिए। अब तक घोषित हो चुके 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। इसी क्रम में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए पूर्व में विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

प्राप्त आवेदनों के परीक्षण और निर्धारित मानकों के आधार पर 156 खिलाड़ियों को पात्र पाया गया। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप, मुख्य सचिव विकास शील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम उपस्थित थीं।

खेल प्रतिभाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर जोर

बैठक में सीएम साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल खिलाड़ियों को सम्मानित करना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत खेल व्यवस्था विकसित करना है, जहां गांव से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाओं की समय रहते पहचान हो, उन्हें आधुनिक प्रशिक्षण, बेहतर संसाधन और प्रतिस्पर्धात्मक अवसर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से खेल गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने तथा खेल प्रतिभाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया।

खेलों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल अधोसंरचना के विस्तार, आधुनिक सुविधाओं के विकास तथा नई खेल अकादमियों की स्थापना की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार करना है, जो राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ और देश का गौरव बढ़ाएं। आज चयनित खिलाड़ी भविष्य में नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर प्रदेश में खेल संस्कृति को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की बैठक

मुख्य सचिव ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर दिया जोर, आपत्तियों के कंडिकावार निराकरण के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दिया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त आपत्तियों का कंडिकावार शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इस वर्ष प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने पर बल दिया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 में अब तक किए गए सामाजिक अंकेक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना एवं बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के निर्माण हेतु विस्तार से चर्चा हुई। सामाजिक अंकेक्षण कार्य में नवाचार एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग पर भी चर्चा हुई। बैठक में सामाजिक अंकेक्षण इकाई के विस्तार हेतु अन्य योजनाओं से निश्चित विकास निधि के निर्धारण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में मनरेगा योजना को संशोधित नवीन योजना वीबीजीरामजी में सामाजिक अंकेक्षण के प्रावधान का अवलोकन करने और आत्मसात करने के प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सहित अन्य योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के कार्यों के संपादन हेतु विभिन्न पदों को नियमानुसार भरने के लिए आवश्यक नियमों के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद अनुमोदन किया गया।

कृषि मंत्री नेताम बोले: आम हर किसी का खास है

रायपुर। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा सोमवार को आयोजित आम महोत्सव उत्साह और गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किया। इस अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी, क्लब के पदाधिकारी, वरिष्ठ एवं युवा पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। पूरे आयोजन के दौरान आत्मीयता, सौहार्द और संवाद का माहौल देखने को मिला।

मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने संबोधन में कहा कि आम हर किसी का खास है। यह केवल फलों का राजा नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों की पसंद और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आम किसानों की मेहनत और प्रकृति की अनमोल देन का प्रतीक भी है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बागवानी फसलों की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मीडिया समाज और शासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने अतिथियों एवं

पत्रकार साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रेस क्लब केवल एक संगठन नहीं, बल्कि पत्रकारों का परिवार है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन पत्रकारों के बीच आपसी भाईचारे, संवाद और सौहार्द को मजबूत करते हैं।

व्यस्त दिनचर्या के बीच ऐसे कार्यक्रम एक-दूसरे से मिलने और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने की जिम्मेदारी भी है।

उन्होंने निष्पक्ष, तथ्यपरक और जिम्मेदार पत्रकारिता पर बल देते हुए कहा कि बदलते समय में पत्रकारों को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने युवा पत्रकारों से सतत अध्ययन, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने का आह्वान किया।

महोत्सव में विभिन्न किस्मों के स्वादिष्ट आम, आम पन्ना, आम की कुल्फी सहित अन्य व्यंजनों का सभी ने आनंद लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और आत्मीय संवाद ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। पत्रकारों ने एक-दूसरे से मुलाकात कर समसामयिक विषयों पर चर्चा की और आयोजन की सराहना की।

कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों एवं पत्रकारों ने रायपुर प्रेस क्लब की इस पहल को सराहा। आम महोत्सव स्वाद, संस्कृति और आपसी सौहार्द का ऐसा संगम बना, जिसने पत्रकार परिवार को एक मंच पर जोड़ते हुए आयोजन को यादगार बना दिया।

रायपुर में टॉपर्स का सम्मान, छात्रा को मिली स्कूटी

29 छात्रों को ?5-5 हजार के चेक, सात स्कूलों के बच्चों को दिए जाएंगे चेक

रायपुर. रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के पंडित रामदयाल तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव के दौरान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 29 मेधावी विद्यार्थियों को ?5-5 हजार के प्रोत्साहन चेक वितरित किए गए। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल की प्रवीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी युक्ता मुखी साहू को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में विद्यालय के लिए 1.50 करोड़ की लागत से अतिरिक्त कक्ष निर्माण और ?19 लाख से खेल मैदान के विकास की स्वीकृति की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि इन कार्यों से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक और खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे पहले महोबा बाजार और मायाराम सुरजन शासकीय विद्यालयों के कुल 57 मेधावी

विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है।

आयोजकों के अनुसार, रायपुर पश्चिम क्षेत्र की शेष सात शालाओं में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी चरणबद्ध तरीके से प्रोत्साहन चेक दिए जाएंगे। इसी क्रम में 3 जुलाई को पंडित गिरजाशंकर विद्यालय में अगला कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विधायक राजेश मूणत ने कहा कि मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है।

उनके अनुसार, अतिरिक्त कक्ष, खेल मैदान और अन्य सुविधाओं के विकास का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।

क्रय समिति भंग, दोबारा टेंडर के आदेश

चरण पादुका खरीद के नियम बदले, हाईकोर्ट ने टेंडर किया निरस्त

रायपुर/बिलासपुर। यह ऐसा मामला है जिसमें लघु वनोपज संघ के अफसरों ने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका खरीदी की शर्तें गुपचुप तरीके से बदल दी। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो चरण पादुका सप्लायर्स ने हाईकोर्ट का रूख किया। कोर्ट ने न सिर्फ टेंडर निरस्त कर दिया, बल्कि क्रय समिति को भंग कर दोबारा टेंडर के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले को सरकार में हलचल मची है।विष्णुदेव साय सरकार ने रमन सिंह सरकार की तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका वितरण योजना को फिर शुरू किया है। सरकार ने 13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को कैनवास के चरण पादुका देने का फैसला किया है। मगर इस बार तेंदूपत्ता सीजन समाप्त होने के बाद भी चरण पादुका की खरीदी पूरी नहीं हो सकी। जबकि सीएम विष्णुदेव साय ने समय पर चरण पादुका वितरण के निर्देश दिए थे।

आरोप है कि चरण पादुका खरीदी के टेंडर में बार-बार बदलाव किए गए और कैजुअल कैनवास वॉकिंग शूज की जगह सेफ्टी फुटवियर श्रेणी में टेंडर जारी कर दिया गया। टेंडर की शर्तें बदले जाने पर सप्लायर कंपनियों ने आपत्ति जताई और अलग-अलग स्तरों पर शिकायत भी की थी। यह बात भी सामने आई है कि

करीब 50 करोड़ रुपये के चरण पादुका खरीदी के नियमों में बदलाव के लिए संचालक मंडल की अनुमति नहीं ली गई। जबकि मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। टेंडर की शर्तों में बदलाव पर दिल्ली की एमएस चरणपादुका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि 4 जून 2026 को जारी जेम टेंडर में ऐसी तकनीकी और वित्तीय पात्रता शर्तें रखी गई थीं, जिनसे केवल सीमित कंपनियां ही पात्र रह जाती थीं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि खरीदी कैजुअल कैनवास वॉकिंग शूज की होनी थी, जबकि जेम पोर्टल पर सेफ्टी फुटवियर श्रेणी का उपयोग किया गया। इस विसंगति के कारण इच्छुक कंपनियों के लिए ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। अदालत ने इसे गंभीर त्रुटि माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछली समान निविदा की तुलना में इस बार पात्रता की शर्तें काफी कठोर कर दी गईं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस और तर्कसंगत आधार प्रस्तुत नहीं किया गया। अदालत के अनुसार ऐसी शर्तें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सीमित करती हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नहीं हैं। अदालत ने टेंडर दस्तावेज तथा अतिरिक्त नियम एवं शर्तों (एटीसी) को निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक खरीद के सिद्धांतों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नई निविदा जारी करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका, वरिष्ठता को लेकर याचिका खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी का प्रारंभिक पदोन्नति आदेश अनियमितताओं के कारण रद्द हो जाता है तो बाद में नए सिरे से मिले प्रमोशन के बाद वह पुराने निरस्त आदेश की तारीख से वरिष्ठता का लाभ नहीं मांग सकता। हाईकोर्ट ने सूरजपुर जिले के पांच मिडिल स्कूल प्रधानपाठकों की याचिका को आधारहीन मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की सिंगल बेंच ने जारी किया है। बता दें कि याचिकाकर्ता शोभनाथ चौबे,अशोक कुमार उपाध्याय, दिनेश कुमार द्विवेदी, संजय कुमार त्रिपाठी और दिनेश कुमार कौशिक सूरजपुर जिले की विभिन्न शासकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में प्रधानपाठक के पद पर कार्यरत हैं। इन सभी शिक्षकों को पहली बार 7 सितंबर 2012 को प्रधानपाठक पद पर पदोन्नति दी गई थी। इन प्रधानपाठकों के खिलाफ अनियमितता का आरोप लगा और इनके प्रारंभिक पदोन्नति आदेश को रद्द कर दिया गया। विभागीय आदेश को सभी प्रधानपाठकों ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे निरस्त करने का आग्रह किया, लेकिन हाईकोर्ट ने की गई कार्रवाई को उचित मानते हुए सभी शिक्षकों की याचिका खारिज कर दी।

स्टोक्स के आसान नहीं होगा संन्यास के बाद मैदान से दूर रहना : सचिन

मुम्बई। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अचानक की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को सोशल मीडिया के जरिये दिये अपने संदेश में कहा है कि उनके लिए मैदान से दूर रहना कठिन होगा।

इस दौरान सचिन ने स्टोक्स के निडर अंदाज और जीत के जज्बे के सथ ही प्रेरणादायक कप्तानी की जमकर प्रशंसा की। स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के बाद अचानक ही संन्यास की घोषणा कर 15 साल के अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का सामापन कर दिया।

तेंदुलकर ने स्टोक्स के खेल को अलविदा कहने के फैसले पर कहा कि ऑलराउंडर ने हर मैच में जो ऊर्जा दिखाई, वह हमेशा ही अद्वितीय रही। उन्होंने स्टोक्स के एक ऑलराउंडर और कप्तान के तौर पर टीम में पड़े प्रभाव की भी सराहना की है। तेंदुलकर ने सोशल मीडिय में लिखा, स्टोक्स, मुझे इसलिए पसंद रहे क्योंकि वह खेल

में काफी ऊर्जा लेकर आते थे। उनका सकारात्मक रवैया, बेखौफ इरादा और दबाव में मैच का रुख पलटने की कला हमेशा याद आयेगी।

एक नई दिशा दी

उन्होंने स्टोक्स को इंग्लैंड के बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक बताया। साथ ही लिखा, एक ऑलराउंडर के तौर पर आप इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में रहे हैं। कप्तान के रूप में आपकी साहसिक रणनीतियां और खेल को सहज समझने की क्षमता ने आपकी टीम को एक नई दिशा दी।

इंग्लैंड के खिलाफ एक दिवसीय सीरीज के लिए नितीश का फिट होना संदिग्ध

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी का इंग्लैंड के खिलाफ 14 जुलाई से शुरू हो रही एकदिवसीय सीरीज में खेलना संदिग्ध नजर आ रहा है। इसका कारण ये है कि नितीश कुमार अभी तक अपनी चोट से उबर नहीं पाये हैं। इसी कारण वह अभी तक अपना रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम भी शुरू नहीं कर पाये हैं जबकि सीरीज शुरू होने में अभी केवल 15 दिन ही शेष हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की मेडिकल टीम ने इस ऑलराउंडर को अभी आराम करने को कहा है जिससे वह फिटनेस हासिल कर सकें।

सूर्यांश या शिवम को मिल सकता है अवसर

गौरतलब है कि इस खिलाड़ी को अफगानिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के दौरान बाएं पैर की मांसपेशी में खिंचाव आ गया था। इस चोट के कारण ही वह दूसरे एकदिवसीय से बाहर रहे थे। तीसरे और अंतिम मुकाबले में उन्होंने दर्द के बावजूद वापसी की थी जिससे उनकी चोट ओर बढ़ गयी। ऐस में दर्द बढ़ने के कारण उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से भी बाहर रहना पड़ा था।

नितीश अगर फिट नहीं होते तो भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। उन्हें अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के फिट नहीं होने के कारण अवसर दिया गया था पर अब वह स्वयं चोटिल हो गये हैं। अगर वह तय समय तक फिट नहीं होते हैं तो युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेडगे को टीम में अवसर मिल सकता है। सूर्यांश ने हाल ही में श्रीलंका में खेली गई एकदिवसीय त्रिकोणीय सीरीज में प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 डेब्यू में भी मौका पाया था, जहां उन्होंने दो ओवर में 25 रन देकर एक विकेट लिया था। लिस्ट-ए क्रिकेट में, शेडगे ने 15 मुकाबलों की 13 पारियों में 21.50 की औसत और 101.97 के स्ट्राइक रेट से 258 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में, उनके नाम 11 विकेट दर्ज हैं, जिसमें एक शानदार चार विकेट हॉल भी शामिल है।वहीं एक दूसरा विकल्प शिवम दुबे हो सकते हैं, जिन्होंने अपनी हालिया आयरलैंड टी20 सीरीज में गेंदबाजी में भी प्रभाव छोड़ा था, जहां उन्होंने तीन विकेट लिए थे।

वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में बदलाव कर सकता है पाकिस्तान

शाहीन, नसीम की जगह पर खुर्रम और उबेद को मिल सकता है अवसर

लाहौर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चयन समिति ने आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम में बदलाव के संकेत दिये हैं। इसी के तहत ही टीम से अनुभवी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को बाहर किया जा सकता है। इनकी जगह घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार, चयन समिति सीनियर गेंदबाजों को टीम में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। शाहीन के अलावा हसन अली और नोमान अली को भी टीम से बाहर किया जा सकता है। वहीं 27 साल के युवा खुर्रम शहजाद और अनकैप्ड खिलाड़ी उबैद शाह को टेस्ट सीरीज में अवसर मिल सकता है।

टीम चयन से जुड़े आकिब जावेद ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को संभावित टीम के बारे में विस्तार से बताया है। नकवी ने टीम की भलाई के लिए कोई भी बड़ा फैसला लेने की पूरी

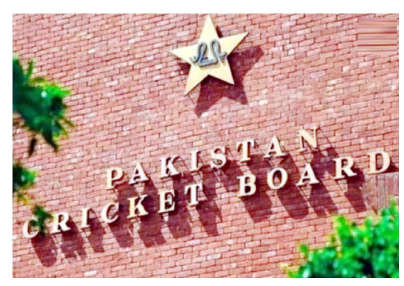

इजाजत दे दी है, जिससे चयनकताओं के पास कड़े फैसले लेने का अधिकार है। कि 36 साल के मुहम्मद अब्बास और 33 साल के मुहम्मद अली जैसे अनुभवी घरेलू गेंदबाजों के अलावा 27 साल के युवा खुर्रम शहजाद और अनकैप्ड खिलाड़ी उबैद शाह को टेस्ट सीरीज में अवसर मिल सकता है। इसके अलावा, 29 साल के आमिर जमाल को तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा।

वहीं शाहीन ने अब तक 34 टेस्ट मैचों में 28.13 की औसत से 126 विकेट लिए हैं। वह पाक टीम के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वहीं, नसीम शाह ने 20 टेस्ट मैचों में 60 विकेट अपने नाम किए हैं। हालांकि ये दोनों ही प्रमुख गेंदबाजों पिछले कुछ समय से फिट नहीं होने से टीम से बाहर हैं। इसके लगातार चोटिल होने से टीम को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि अब चयनकर्ता एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर विचार कर रहे हैं। मुहम्मद अली और मुहम्मद अब्बास दोनों इस समय इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं और वेस्टइंडीज सीरीज शुरू होने से पहले टीम में शामिल हो जाएंगे।

वेस्टइंडीज दौरे का पहला टेस्ट त्रिनिदाद के तारोबा में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित होगा।

बेल्जियम दौरे में शीर्ष यूरोपीय टीमों से खेलेगी भारतीय जूनियर हॉकी टीम

नई दिल्ली। भारतीय जूनियर पुरुष अंडर-21 हॉकी टीम 5 से 18 जुलाई तक बेल्जियम दौरे पर रहेगी। इसमें डिफेंडर अनमोल इक्का की कप्तानी में 22 सदस्यीय टीम को बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड जैसी शीर्ष यूरोपीय टीमों से खेलना है।

टीम के नए मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयेज के मार्गदर्शन में ये भारतीय टीम का पहला दौरा है। इस दौरे से टीम को इस साल के अंत में होने वाले जूनियर एशिया कप की तैयारियों में भी सहायता मिलेगी।

यूरोपीय टीमों के खिलाफ होने वाले इस दौरे में भारतीय टीमके युवा खिलाड़ियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिलेगा। यह टीम को अपने

डिफेंडर अनमोल करेंगे कप्तानी

संयोजन, रणनीति और खेल के विभिन्न पहलुओं को आंकने का भी अवसर देगा। इससे युवा खिलाड़ियों को उच्च दबाव वाले मैचों में प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता को विकसित करने में मदद मिलेगी, जो भविष्य के बड़े टूर्नामेंटों के लिए अहम है। इस दौरे पर भारतीय टीम कुल छह चुनौतीपूर्ण मुकाबले खेलेगी। टीम ऑस्ट्रिया और मेजबान बेल्जियम के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी, जबकि जर्मनी और नीदरलैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ एक-एक मुकाबला होगा। भारतीय टीम 7 और 8 जुलाई कोझ ऑस्ट्रिया, 10 जुलाई को बेल्जियम, 13 जुलाई को जर्मनी, 14 जुलाई को बेल्जियम, 17 जुलाई को नीदरलैंड से खेलेगी।

अब ऑस्ट्रेलिया की जगह पुर्तगाल से खेलेंगे हेनरिक्स

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर मोइसेस हेनरिक्स ने कहा है कि अब वह अपनी ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अपने जन्मस्थान पुर्तगाल की ओर से खेलेंगे। हेनरिक्स का कहना है कि उनका लक्ष्य 2028 टी20 विश्वकप में पुर्तगाल को क्वालिफाई कराना है। हेनरिक्स के इस कदम से एसोसिएट टीम पुर्तगाल को काफी लाभ होगा। इससे उसके लिए वैश्विक मंच पर पहचान बनाना आसान होगा। गौरतलब है कि हेनरिक्स का जन्म पुर्तगाल के मदीरा द्वीप पर हुआ था पर वह क्रिकेट करियर के लिए ऑस्ट्रेलिया आ गये थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के टेस्ट, एकदिवसीय और टी20 तीनों प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला है। अगस्त 2021 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। आईसीसी के नियमों के अनुसार, किसी पूर्वकालिक सदस्य देश से एसोसिएट राष्ट्र के लिए खेलने से पहले खिलाड़ी को तीन साल का अनिवार्य अंतराल पूरा करना होता है। यह

अवधि अब पूरी हो चुकी है, जिसके बाद हेनरिक्स पुर्तगाल के लिए खेलने के योग्य हो गए हैं।

अब हेनरिक्स फिनलैंड में होने वाले यूरोप सब-रीजनल क्वालिफायर में पुर्तगाल की ओर से मैदान पर उतरेंगे। यह क्वालिफायर 2028 के टीम 20 विश्व कप के यूरोपीय क्वालिफिकेशन चरण में जगह बनाने के लिए जरुरी है। यूरोप से मौजूदा आईसीस रैंकिंग के आधार पर पहले से मौजूद टीमों के अलावा दो नई टीमें अगले चरण के लिए क्वालिफाई करेंगी। हेनरिक्स को उम्मीद है कि वह अपने अनुभव और कौशल से पुर्तगाल को पहली बार टी20 विश्व कप तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।अपने करियर में अब तक 301 टी20 मुकाबले खेल चुके हेनरिक्स ने 5,746 रन बनाए हैं, जिसमें 27 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 120 विकेट भी झटके हैं। उनका यह विशाल अनुभव और ऑलराउंडर क्षमता अब पुर्तगाल क्रिकेट के लिए एक बड़ी संपत्ति साबित होगी।

ऐपल का सीसीआई पर गंभीर आरोप, जांच में हुई कॉपी-पेस्ट

प्रतिस्पर्धियों के दावों की हूबहू नकल का दावा, 21 जुलाई को होगी अहम सुनवाई

नई दिल्ली। ऐपल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) पर एक गंभीर आरोप लगाया है।

कंपनी ने कहा है कि उसके खिलाफ एंटीट्रस्ट जांच में, सीसीआई के जांचकताओं ने प्रतिस्पर्धियों के दावों को हूबहू कॉपी-पेस्ट किया है, जिससे प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन का निष्कर्ष निकाला गया। 25 जून को सामने आई इस जानकारी ने ऐपल और सीसीआई के बीच चल रहे विवाद को और गहरा कर दिया है। ऐपल ने इन निष्कर्षों को रद्द करने की मांग की है। साल 2024 में,

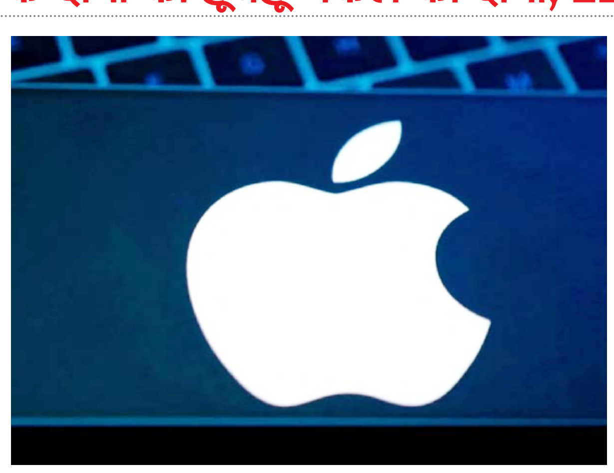

सीसीआई के जांचकताओं ने एक रिपोर्ट में कहा था कि ऐपल ने अपने आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर गलत व्यवहार किया और अपने पेमेंट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य बनाया। ऐपल ने इन आरोपों का

कंपनी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निष्कर्षों को रद्द करने की मांग की

खंडन करते हुए कहा कि भारत में उसकी बाजार हिस्सेदारी 6% से भी कम है। कंपनी का तर्क है कि जांच के निष्कर्ष सीसीआई के स्वतंत्र विश्लेषण के बजाय मैच, फोनपे और पेटीएम जैसे प्रतिस्पर्धियों के दावों पर आधारित हैं।

ऐपल ने दावा किया कि सीसीआई के जांच दल ने इन बयानों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कंपनी ने चेतावनी दी कि उसके ऐप स्टोर में मजबूरन किए गए किसी भी बदलाव से उसके एकीकृत कारोबारी मॉडल में बाधा आ सकती है, नियामकीय अनिश्चितता पैदा हो सकती है और भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेश हतोत्साहित हो सकता है।

ऐपल ने सीसीआई द्वारा किसी भी जुमार्ने या सुधारात्मक उपायों का विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि 2023 में गूगल ने भी ऐसे ही तर्क दिए थे, लेकिन सीसीआई ने उसे अपने एंड्रॉइड सिस्टम को बढ़ावा देने के तरीके में बदलाव करने पर मजबूर किया था। इस मामले में 21 जुलाई को सभी पक्षों के साथ एक बंद कमरे में सुनवाई होगी।

बड़े ऑर्डर से सुजलॉन के शेयर में उछाल, जानकार ने कहा 72 तक जाएगा

मुंबई। मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों में मंगलवार को 2 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज हुआ। कंपनी को सनश्योर एनर्जी से 105 मेगावाट की विंड एनर्जी परियोजना का ठेका मिला है, इसके बाद इसके शेयर पिछली क्लोजिंग 57.19 के मुकाबले बढ़कर 58.15 रुपये तक पहुंच गए। यह सुजलॉन के नए और भारत के सबसे ऊंचे व शक्तिशाली एस 175 टर्बाइन के लिए पहला कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी ने बताया कि 5.0 मेगावाट क्षमता के एस 175 टर्बाइन पेश किए जाने के महज दो सप्ताह के भीतर यह महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है।

यह सनश्योर से सुजलॉन को पिछले 14 महीने से भी कम समय में मिला तीसरा ठेका है, जिससे दोनों कंपनियों के बीच कुल साझेदारी 400.8 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक के बीजापुर में 21 एस175 पवन टर्बाइन जनरेटर की आपूर्ति, स्थापना, चालू करना और मेंटेनेंस किया जाएगा। सुजलॉन समूह के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने सनश्योर के साथ अपनी मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया।

इस बड़े ऑर्डर के बाद सुजलॉन के शेयर में आगे भी उछाल की संभावना प्रबल है। घरेलू ब्रोकरेज ने भारतीय विंड एनर्जी मार्केट में सुजलॉन की मजबूत स्थिति और काम पूरा करने के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर 65 के टारगेट प्राइस के साथ बाय रेटिंग बरकरार रखी है।

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 फिर शीर्ष स्थान पर

नई दिल्ली। भारतीय दो पहिया वाहन बाजार में मई 2026 में 350सीसी से 450सीसी बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 ने एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। युवाओं के बीच इस सेगमेंट की बाइक्स का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और क्लासिक 350

उनकी पहली पसंद बनी हुई है। इस देसी बाइक को 34,594 ग्राहकों ने खरीदा, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 20.84 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दशार्ता है। रॉयल एनफील्ड का जलवा केवल क्लासिक 350 तक ही सीमित नहीं है। बिक्री की इस सूची में दूसरे स्थान पर रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 रही, जिसने 23,372 यूनिट्स की बिक्री के साथ 35.26 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। तीसरे पायदान पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 ने अपनी जगह बनाई, जिसके 20,418 यूनिट्स बिके और 27.84 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। रॉयल एनफील्ड मिटिओर 350 भी 7,697 यूनिट्स के साथ चौथे स्थान पर रही, जो ब्रांड के मजबूत प्रदर्शन को दशार्ता है। अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में जावा-येज्दी और बीएसए के संयुक्त आंकड़ों ने 4,447 यूनिट्स की बिक्री के साथ 103.06 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की। वहीं, नई ट्रायम्फ 350 ने बाजार में अपनी दमदार एंट्री करते हुए 4,348 यूनिट्स बेचीं। होंडा सीबी 350 और होंडा हाईनेस 350 ने भी क्रमश: 4,178 और 2,128 यूनिट्स के साथ अच्छी बिक्री दर्ज की।

जूम 125 एडवेंचर स्कूटर का डिजाइन पेटेंट इंटरनेट पर लीक

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी की अपकमिंग जूम 125 एडवेंचर स्कूटर का डिजाइन पेटेंट इंटरनेट पर लीक हो गया है, जो देखने में बिल्कुल प्रोडक्शन-रेडी लग रहा है। यह लीक कंपनी के एक बड़े मास्टरस्ट्रोक की ओर इशारा करता है, जिसका उद्देश्य स्कूटर सेगमेंट में हीरो की स्थिति को मजबूत करना है। यह नया एडवेंचर स्कूटर 2024 ईआईसीएम शो में दिखाए गए जूम 125 एडवेंचर कॉन्सेप्ट पर आधारित है। उस कॉन्सेप्ट मॉडल में हीरो ने अपनी मशहूर डकार रैली थीम का इस्तेमाल किया था। लीक हुई इमेज के अनुसार, इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। एप्रन एरिया और साइड बॉडी की सुरक्षा के लिए एक मजबूत लाल रंग का क्रैश गार्ड दिया गया है। सामने वाले रेगुलर फेंडर को हटाकर बाइक जैसा बीक फेंडर लगाया गया है।

अडानी ने विझिनजम पोर्ट में बेची 49 प्रतिशत हिस्सेदारी, शेयर में उछाल

मुंबई। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने केरल स्थित विझिनजम पोर्ट प्रोजेक्ट में अपनी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (टीआईएल) को 1.397 अरब डालर में बेचने का समझौता किया है। यह डील एसेट के 2.85 अरब डालर के मूल्यांकन पर आधारित है। टीआईएल, जो मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी (एमएससी) की टर्मिनल चलाने वाली शाखा है, इस अधिग्रहण के साथ भारतीय पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा विदेशी निजी निवेश कर रही है। इस सौदे के बाद भी, एपीएसईजेड विझिनजम पोर्ट में 51प्रतिशत हिस्सेदारी बनाए रखेगा, बोर्ड पर उसका नियंत्रण रहेगा और वह

इस अपनी सहायक कंपनी के रूप में ही रखेगा। यह एपीएसईजेड और टीआईएल के बीच मुंद्रा और एन्नोर कंटेनर टर्मिनलों में उनके सफल जॉइंट वेंचर के बाद तीसरा बड़ा सहयोग है। इस महत्वपूर्ण खबर के बीच, मंगलवार को अडानी पोर्ट्स के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन कंपनी का शेयर 2 प्रतिशत से अधिक चढ़कर 1,815.80 रुपये तक पहुंच गया, जो इसके 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर 1,857.60 रुपये के करीब है।

एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ, अश्विनी गुप्ता ने बताया कि विझिनजम पोर्ट एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में उभरा है और संचालन शुरू होने के मात्र 18 महीनों में 20 लाख ट्वेंटी-फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स (टीईयूएस) का माल संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि टीआईएल, जो दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल परिचालकों में से एक है, के साथ यह साझेदारी कार्गो विजिबिलिटी को बेहतर करेगी, ट्रांसशिपमेंट वॉल्यूम बढ़ाएगी और पूर्वी अफ्रीकी तथा बांग्लादेश के व्यापार मार्गों तक पहुंच को मजबूत करेगी।

विझिनजम भारत का पहला डीप-ड्राफ्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसकी सालाना हैंडलिंग क्षमता 1.6 मिलियन टीईयूएस है। यह पोर्ट यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम समुद्री मार्ग से रणनीतिक रूप से केवल 10 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। दिसंबर 2028 तक इसके विस्तार के बाद, पोर्ट की क्षमता 3.5 गुना बढ़कर 5.7 मिलियन टीईयूएस हो जाएगी।

उज्जैन अब लिख रहा है औद्योगिक विस्तार की नई इबारत : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज का दिन मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उज्जैन जो पहले से ही धार्मिक नगरी के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अब औद्योगिक विस्तार की भी नई इबारत भी लिख रहा है। हमारे लिए यह अत्यंत गौरवशाली क्षण है। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से मध्यप्रदेश ग्लोबल निवेश का हब बन रहा है। औद्योगिक विस्तारीकरण से प्रदेश के कई युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को उज्जैन के विक्रम उद्योगपुरी के ग्राम नरवर स्थित 1266 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित पेप्सिको फ्लेवर कंसनट्रेट निर्माण संयंत्र के लोकार्पण समारोह को भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य के शासन काल में उज्जैन नगरी विश्व के सबसे समृद्ध और सम्पन्न व्यापारिक नगरों में गिनी जाती थी। हमारा लक्ष्य है कि उज्जैन नगरी उसी वैभव को पुनः प्राप्त करें। आस्था के साथ उज्जैन उद्योग निवेश और रोजगार का भी अग्रणी केंद्र बनें।

देश का फ्लेवर कंसनट्रेट का दूसरा संयंत्र उज्जैन में हुआ प्रारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्योग स्थापित कर मालवा की प्रगति को निरंतर गति दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्यप्रदेश का सफल आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की इस अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का शुभारंभ होने पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत में इस विशिष्ट और उच्च तकनीकी फ्लेवर कंसनट्रेट निर्माण के केवल 02 संयंत्र है, जिनमें से 01 आज से उज्जैन में प्रारंभ हो रहा है। विक्रम उद्योगपुरी में 22 एकड़ क्षेत्र में 1226 करोड़ रुपए के निवेश से इस संयंत्र की स्थापना की गई है। पूरी तरह ऑटोमेशन पर आधारित इस संयंत्र से 800 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। यह नया संयंत्र भारत में कंपनी की विनिर्माण क्षमता को और मजबूत करेगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने के साथ क्षेत्र में सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पेप्सिको इंडिया और साउथ एशिया के सीईओ श्री जागृत कोटेचा ने कहा कि हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का क्षण है कि हमारी कंपनी को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में म.प्र. शासन के सहयोग से संयंत्र स्थापित करने का अवसर मिला। उन्होंने इसके लिये मुख्यमंत्री डॉ. यादव, म.प्र. शासन और एमपीआईडीसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

राज्यसभा सदस्य श्री बाल योगी उमेंश नाथ जी महाराज ने कहा कि उज्जैनवासियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विशेष प्रयासों से औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। नवीन उद्योगों की स्थापना हो रही है। उज्जैन नगरी धार्मिक पहचान के साथ औद्योगिक और निवेश केंद्र के रूप में भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगी।

कार्यक्रम में म.प्र. हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम जैन, नगर निगम सभापती श्रीमती कलावती यादव, प्रबंध निर्देशक एमपीआईडीसी श्री चंद्रमौली शुक्ला, एमपीआईडीसी उज्जैन के कार्यकारी निदेशक श्री राजेश राठौर, पेप्सिको कंपनी के श्री हरदीप भाटिया, कंपनी के सीईओ इंटरनेशनल बेवरेजेस श्री यूजीन विलेमसेन, जनरल मैनेजर एवं सीनियर वाईस प्रेसिडेंट श्री इवान नॉर्टन सहित नागरिक उपस्थित थे।

पूर्वजों द्वारा निर्मित जल संरचनाओं को सहेजना हमारा दायित्व

जल से ही प्रकृति का उद्भव और जीवन का विकासः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल से ही प्रकृति का उद्भव और जीवन का विकास है। सबसे पहले पृथ्वी पर जलचर आए। जल से ही जीवन है। जल तत्व में सभी तत्व समाहित हैं। हम जब जल संरचनाओं को देखते हैं तो हमारा मन आनंद से भर जाता है। जल से स्नान के बाद हमें ताजगी मिलती है। हमारे पूर्वजों ने जल के महत्व को समझा और निरंतर जल संरचनाओं का निर्माण किया। आज हमारा दायित्व है कि हम उन सब का संरक्षण करें एवं उन्हें सहेजें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में भी गत 3 वर्षों से यह अभियान वृहद रूप से जन सहयोग से चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में जल संरचनाओं का संरक्षण एवं पुनरुद्धार किया गया है। आज यहां जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन कार्यक्रम है, परंतु मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल अलनीनो के प्रभाव से कम वर्षा का अनुमान है, इसलिये प्रदेश में अमृत सरोवर रैन वॉटर हार्वेस्टिंग, नदी संरक्षण जैसे जल स्रोतों के संरक्षण कार्य निरंतर जारी रहेंगे। गत 19 मार्च से लगभग 100 दिन प्रदेश में चले जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत प्रदेश में जल संवर्धन के 10 हजार 514 करोड़ की लागत से 3 लाख 63 हजार कार्य कराए गए। इन कार्यों में भरपूर जन समर्थन एवं जन सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को राजगढ़ जिले के भैंसवा माता क्षेत्र में प्रदेश में चले जल गंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 252 करोड़ 65 लाख रुपए के 31 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने भैंसवा माता क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या-पूजन एवं दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में पंच तत्वों, विशेष रूप से जल का विशेष महत्व है। हमारे यहां हर पवित्र कार्य जल के साथ ही होता है। प्रसिद्ध कवि रहीम ने भी पानी की महत्ता बताई। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राजगढ़ जिले में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में चिन्हित छह सर्वश्रेष्ठ जिलों में राजगढ़ जिले का भी नाम शामिल है। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधितों को बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों की समृद्धि का आधार सिंचाई की सुविधा है। गत 20 वर्षों में हमारी सरकारों में प्रदेश में सिंचाई के रकबे में तेजी से वृद्धि हुई है। हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारा संकल्प है और हम उसे पूरा कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम भी दिलवाया जा रहा है। हमारी सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2625 रुपए कर दिया है। किसानों को किसान सम्मन निधि दी जाती है। हमारी सवा करोड़ बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है। बच्चों को उनकी शिक्षा के लिए हर संभव सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जो उत्कृष्ट शिक्षा के केंद्र हैं। ये विद्यालय हमें सांदीपनि ऋषि, भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की याद दिलाते हैं। भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की निस्वार्थ मित्रता एवं प्रेम को आज पूरी दुनिया याद करती है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा मेला, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतिबिंब, सिंहस्थ उज्जैन मध्यप्रदेश में आयोजित होता है। इसे भव्य, दिव्य बनाने और श्रद्धालुओं के स्नान आदि की सुविधाओं के लिए उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के स्वच्छ एवं पावन जल में सहजता एवं सुविधापूर्वक, बिना किसी परेशानी के स्नान एवं उज्जैन तीर्थ के दर्शन हो सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा सारंगपुर क्षेत्र के विकास के लिए की गई प्रमुख घोषणाएं

1. सारंगपुर नगर के अंदर जीर्ण-शीर्ण पड़े शासकीय भवनों एवं आवासों का रेडेंसिफिकेशन योजना अंतर्गत पुनर्निर्माण किया जाएगा।
2. शासन संधारित अंबे माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
3. नवीन स्वीकृत फोर लेन में हाउसिंग बोर्ड द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी।
4. पचोर और सारंगपुर क्षेत्र में विकास के लिए सड़को का निर्माण किया जाएगा।
5. सारंगपुर-संडावता मार्ग पर उतावली नदी पर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा।
6. करौंदी से हीरापुरा तक 2 किमी सड़क के निर्माण सहित आवश्यक अन्य सभी मार्गों का निर्माण किया जाएगा।
7. भैंसवा माता लोक के विकास, निर्माण और सौंदर्गीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में अब तक हुए सभी कार्य प्रामाणिकता के साथ हुए है। इस साल बारिश के मौसम में कम वर्षा का अनुमान है इसलिए जल संचयन और जल स्त्रोतों का संरक्षण निरंतर जारी रखना आवश्यक है। हम सभी को पानी की एक-एक बूंद संचित कर भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है। राज्य सरकार और सभी अधिकारी-कर्मचारी जनभागीदारी से जल संरक्षण के प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का मंत्री श्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन को मां भैंसवा के पवित्र स्थल पर रखने के लिए आभार व्यक्त किया।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. गौतम टेटवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाएं को बढ़ाने के लिए भागीरथी प्रयास किए हैं। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान-2026 के अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जल संरक्षण के इस अभियान में पंचायतों को जोड़कर जनभागीदारी से कुएं, बावड़ी, तालाब, नदियों की सफाई और प्राचीन जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार किया गया है। राज्यमंत्री श्री टेटवाल ने सांदीपनि विद्यालय, पीकेसी परियोजना से पानी, भैंसवा माता लोक निर्माण सहित अनेक निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया।

सांसद श्री रोमल नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में विरासत से विकास की यात्रा अनवरत जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पर भगवान बाबा महाकाल और मां बिजासन की विशेष कृपा है। सारंगपुर में 251 करोड़ रूपए की लागत से भैंसवा माता धार्मिक स्थल शेत्र का विकास किया जा रहा है' रोजगार के स्थानीय साधन उपलब्ध कराते हुए यहां बहनों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। साथ ही संस्कृत वैदिक पाठशाला, गोशाला, योग केंद्र और सामुदायिक भवन तैयार करने के कार्य किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के यह प्रयास समाज को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर विकासखण्ड में प्रसिद्ध भैंसवा माता मंदिर में दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने दूधतलाई पर पहुंचकर पवित्र गंगा-पूजन किया। पर्यावरण संरक्षण और जीव-दया के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पशुओं को चारा खिलाया और गौ-पूजन भी किया। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत बेलपत्र का पौध-रोपण किया और नागरिकों को हरित पर्यावरण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई 'जल गंगा संवर्धन अभियान 2.0' की विकास प्रदर्शनी का गहन अवलोकन किया और जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पारंपरिक रूप से 'कन्या पाद पूजन' और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत राजगढ़ जिले में हुए विभिन्न विकास कार्यों और उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष पुस्तिका का विमोचन भी किया। साथ ही राजगढ़ की स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को वैश्विक पटल पर लाने के उद्देश्य से जिला पुरातत्व एवं राजगढ़ पर्यटन पर केंद्रित एक विशेष प्रमोशनल फिल्म, आकर्षक कॉफी टेबल बुक तथा आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स का अनावरण भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत मंच से हितग्राहियों को 21 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक की राशि के लाभ और वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए। इसके तहत मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 405 समूहों को कुल 20 करोड़ रुपये का बैंक ऋण वितरित किया गया, जिसमें श्रीमती कृष्णा भिलाला, श्रीमती रानी भिलाला और श्रीमती माया वर्मा प्रमुख रूप से लाभान्वित हुईं। पशुपालन विभाग की डॉ.भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत हितग्राही श्री मंगलेश पाटीदार को 36 लाख रुपये और श्रीमती विमल यादव को 35.70 लाख रुपये की राशि के हितलाभ सौंपे गए। इसी तरह, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत श्री कार्तिक माहेश्वरी (पार्वती एंटरप्राइजेस) को 22.50 लाख रुपये और श्री राहुल परमार (अयोध्या ऑयल मिल) को 27.37 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत किराना व्यवसाय के लिए श्री मनीष कुमार गुप्ता को 10 लाख रुपये और डेयरी प्रोडक्ट के लिए श्री हितेष शर्मा को 5 लाख रुपये के चेक प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मनोज पाटीदार और बलराम को मिनी स्प्रिंकलर सेट के लिए प्रत्येक को 79 हजार 545 रुपये का अनुदान दिया गया, जबकि पी।एम। स्वनिधि योजना, नगरीय आवास विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रियंका जाटव, मांगी बाई, पूजा साहू सहित अन्य हितग्राहियों को 50 हजार रुपये के चेक और गृह प्रवेश के आवंटन पत्र वितरित किए गए।

दुर्लभ वन्य-जीव सैंडबोआ की तस्करी के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

भोपाल। दुर्लभ वन्य-जीव सैंडबोआ की तस्करी से जुड़े 10 वर्ष पुराने प्रकरण में माननीय तेईसवें अपर सत्र न्यायालय, भोपाल ने आरोपी प्रतीक सिंह बोहरा को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश और एसटीएफ पुलिस ने 7 जनवरी 2016 को संयुक्त कार्रवाई में मीनाल एन्क्लेव, गुलमोहर क्षेत्र के पास एक वाहन से सैंडबोआ बरामद कर आरोपी अमन उर्फ हनी, लोकेश उर्फ मलिक, विजय उर्फ विज्जू, प्रतीक सिंह बोहरा और ब्रजेश पटेल को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया था। वर्ष 2022 में इसी प्रकरण के अन्य आरोपी अमन सक्सेना, लोकेश मेहरा, विजय वर्मा और अमित चौहान को भी तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

आरोपी प्रतीक सिंह बोहरा लंबे समय से फरार था, उसे एसटीएफ पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन से प्राप्त सैंडबोआ के वीडियो तथा फॉरेंसिक प्रयोगशाला की वैज्ञानिक जांच को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से एसटीएफ पुलिस के साथ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश के अधिकारियों ने सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए। विशेष लोक अभियोजकों की प्रभावी पैरवी भी इस प्रकरण में महत्वपूर्ण रही।

30 जून तक 2 लाख 93 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने लिया प्रवेश

भोपाल। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित ई-प्रवेश पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 30 जून 2026 तक प्रदेशभर में 5,48,778 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इनमें से 4,68,539 विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन पूर्ण हो चुका है तथा 2, 93, 257 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

पिछले वर्ष कि तुलना में इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। प्रवेश में 42.03 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 30 जून तक 2,06,482 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया था, जबकि इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 2,93,257 हो गई है। यानी एक वर्ष में 86,775 अधिक विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई गई पारदर्शी, ऑनलाइन, सरल एवं विद्यार्थी-केंद्रित प्रवेश व्यवस्था, महाविद्यालयों में समयबद्ध दस्तावेज सत्यापन तथा प्रभावी काउंसलिंग व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

विद्यार्थियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विभाग ने रिक्त सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब जिन शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में सीटें रिक्त हैं, वहाँ इच्छुक विद्यार्थी सीधे संबंधित महाविद्यालय पहुँचकर उसी दिन पंजीयन, दस्तावेज सत्यापन एवं सीट आवंटन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करा सकेंगे। सीट आवंटित होने के तुरंत बाद विद्यार्थी उसी दिन निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों को किसी अतिरिक्त चरण अथवा प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा और रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया तेजी से पूर्ण हो सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी पात्र विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम शासकीय अथवा अशासकीय महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों की जानकारी प्राप्त कर इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएँ तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना प्रवेश सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में भारतीयता का होगा नवोदयः राज्यपाल श्री पटेल

नई पीढ़ी को संस्कृत और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना समय की आवश्यकता

भोपाल। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों को उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में भारतीयता का समावेश विकसित भारत की सुदृढ़ आधारशिला है। भारतीय संस्कृति, संस्कार और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन से आत्मनिर्भर, संस्कारित और विकसित भारत का निर्माण होगा।

राज्यपाल श्री पटेल मंगलवार को उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकादमी में आयोजित महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के छठवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में पीएचडी की 21 उपाधियों के साथ ही कुल 1 हजार 303 उपाधियां प्रदान की गई। विद्यार्थियों को 16 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक तथा 13 कांस्य पदक, कुल 42 पदक प्रदान किए गए। राज्यपाल श्री पटेल ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्राचीन काल में शिक्षा का केन्द्र हमारा देश था। विदेशों से अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते थे। आज हमारे बच्चे विदेश जा रहे है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा से विकसित भारत @2047 बनाने की पहल की है। विकसित भारत में बच्चों को शिक्षा के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि संस्कृत की पहचान विश्व में स्थापित करने की दिशा में प्रभावी पहल करें क्योंकि अच्छे संस्कारों के अंकुरण से ही संस्कृति का रक्षण संभव है। आज की पीढ़ी को संस्कृत और परंपराओं के ज्ञान की आवश्यकता बताते हुए कहा कि प्राचीन ज्ञान का बोध संस्कृत के माध्यम से ही संभव हो सकता है। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के महान ग्रंथों के अध्ययन के लिए बच्चों को प्रेरित और संस्कारित आचरण की वैज्ञानिकता के बारे में बताने की भी जरूरत बताई है।

राज्यपाल श्री पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में सफलता के बाद भी अपने माता-पिता को कभी नहीं भूलें, क्योंकि उनकी बदौलत ही हमारा जीवन है। राज्यपाल श्री पटेल ने माता-पिता के प्रति सम्मान, भारतीय परंपराओं के प्रति आस्था तथा चरित्र निर्माण को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा कि आज घरों में ह्यमातृ छायाह्न और ह्यपितृ छायाह्न लिखा तो होता है, लेकिन घरों में बुजुर्ग माता-पिता नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे संस्कारों से ही संस्कृति सुरक्षित रहती है। संस्कृति संरक्षण से ही भारत को विकसित बनाने का स्वप्न साकार होगा।

भारत होगा दुनिया को उर्जा की पूर्ति करने वाला केंद्र

उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और मान्यताओं को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की वैज्ञानिकता को समझा था। उदाहरण देते हुए बताया कि सौर मंडल में सूर्य की शक्ति की वैज्ञानिकता का प्रतीक सूर्य देव को प्रणाम करने और अर्ध्य देने की परंपराएं है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में उर्जा को लेकर विवाद हो रहा है। वर्ष 2047 तक भारत दुनिया की उर्जा पूर्ति का केन्द्र और विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा में शामिल करने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। समारोह में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठानम् पुणे के संस्थापक स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज को महामहोपाध्याय (डी.लिट.) और श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो. रमेश कुमार पाण्डेय को विद्यावाचस्पति (डी.लिट.)की मानद उपाधि प्रदान की गई।

कार्यक्रम में दीक्षांत भाषण सारस्वत अतिथि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी ने दिया। कार्यक्रम को स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज ने भी संबोधित किया। कुलगुरु प्रो. शिवशंकर मिश्र ने स्वागत भाषण देते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियां बताई। समारोह का संचालन डॉ. उपेंद्र भार्गव ने किया और आभार कुल सचिव डॉ. दिलीप सोनी ने माना। समारोह के प्रारंभ में अकादमिक शोभायात्रा निकाली गई। राष्ट्रगान, विश्वविद्यालय कुलगान का गायन हुआ। राज्यपाल सहित सभी अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

उड़ीसा के पेयजल मंत्री नायक ने जल निगम की नवाचार आधारित कार्यप्रणाली की सराहना की

भोपाल। उड़ीसा के पंचायती राज एवं पेयजल मंत्री श्री रबी नारायण नायक के नेतृत्व में आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया।

प्रतिनिधिमंडल ने निगम की संस्थागत व्यवस्था, परियोजना क्रियान्वयन प्रणाली, तकनीक आधारित मॉनिटरिंग, संचालन एवं संधारण (ओ एंड एम), वित्तीय प्रबंधन तथा मानव संसाधन विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री नायक ने मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा अपनाई गई आधुनिक और नवाचार आधारित व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि इनमें से कई व्यवस्थाओं को उड़ीसा में भी लागू करेंगे।

प्रबंध संचालक, म.प्र. जल निगम श्री के.वी.एस. चौधरी ने प्रतिनिधिमंडल को जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में संचालित ग्रामीण नल-जल योजनाओं की प्रगति, डिजिटल मॉनिटरिंग व्यवस्था, रियल टाइम निगरानी प्रणाली, परियोजनाओं के संचालन एवं संधारण मॉडल, ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपयोग एवं विद्युत भुगतान की व्यवस्था, क्षमता विकास (ट्रेनिंग) कार्यक्रमों तथा तकनीक आधारित प्रबंधन प्रणाली पर विस्तृत जानकारी साझा की। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश जल निगम के संस्थागत ढांचे, सुशासन, वित्तीय मॉडल, परियोजना क्रियान्वयन, 'जल रेखा' एवं 'पंचायत दर्पण' जैसे तकनीकी नवाचारों की कार्यप्रणाली तथा ग्रामीण जलापूर्ति प्रबंधन की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इन व्यवस्थाओं को ग्रामीण पेयजल सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए उपयोगी बताते हुए इनके व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी भी प्राप्त की।

बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच संस्थागत ढांचे, वित्तीय स्वायत्तता, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, गुणवत्ता नियंत्रण, डिजिटल गवर्नेंस तथा भविष्य में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। उड़ीसा के पेयजल मंत्री श्री नायक ने कहा कि मध्यप्रदेश जल निगम ने जिस पेशेवर एवं परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली को विकसित किया है, वह अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणादायी मॉडल है। अध्ययन भ्रमण के माध्यम से प्राप्त अनुभव उड़ीसा में ग्रामीण जल प्रदाय व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

उड़ीसा के प्रतिनिधिमंडल में पंचायती राज एवं पेयजल विभाग के आयुक्त-सह-सचिव श्री गिरिश एस.एन., पेयजल एवं स्वच्छता निदेशक श्री विनीत भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव श्रीमती मधुस्मिता सामल, इंजीनियर-इन-चीफ श्री रत्नाकर सियाल सहित विभाग एवं स्टेट पीएमयू के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। बैठक में मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी साझा की।

पुलिस मुख्यालय परिवार द्वारा 11 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई

भोपाल। पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से माह जून में सेवानिवृत्त 11 कर्मचारियों को पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने मंगलवार को भावभीनी विदाई दी। पुलिस महानिदेशक ने सभी को पौधे एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए और उनके स्वस्थ एवं सुखी जीवन की कामना की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके विभिन्न स्वत्व (क्लेम) भुगतान के आदेश भी प्रदान किए गये।

नवीन पुलिस मुख्यालय भवन कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित विदाई समारोह में विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आदर्श कटियार, श्री पंकज श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सोलोमन यश कुमार मिंज, पुलिस महानिरीक्षक श्री हरिनारायणचारी मिश्र एवं अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिजन उपस्थित थे।

संपादकः अली आदिल खान द्वारा सांई प्रिंटिंग प्रेस डी-85, न्यू अशोक अगर, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, यूपी से मुद्रित कराकर सी-148, साउथ मोती वाग,पो. चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 से प्रकाशित किया।
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।